[Sardar Jagjit Singh Aurora]

be stopped. It is important that very capable and honest officers are posted both for administrative purposes as well as for intelligence duty ; otherwise we may find the situation growing from bad to worse and we get further embroiled in it. Thank you very much.

STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF CONTINUANCE IN FORCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RELATION TO JAMMU AND KASHMIR – Contd.

श्री विश्वजय सिंह (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, कल मैंने जहां अपनी बात खत्म की थी, आज फिर वहीं से शुरू करना चाहूंगा । कल मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को अर्ज कर रहा था कि काश्मीर के सवाल पर हम कोई एक निश्चित राय इस देश में नहीं बना पाए अब तक । पिछले 40–42 वर्षों से एकाध पार्टी को छोड़कर काश्मीर के मामले में एक आम सहमति चली आ रही थी देश के अंदर और उसी के तहत इस देश के लोगों में जो हम अपनी नीति बनाए हुए थे धारा–370 के तहत, वह सर्वमान्य हो रही थी। मगर घटनाओं का क्रम कुछ इस तरह से बदलता जा रहा है कि पिछले दो-तीन वर्षों से जिससे कि यह देश मजबूर हो रहा है, देश के लोग मजबूर हो रहे हैं फिर से काश्मीर के बारे में एक नयी दिशा से, एक नये तरीके से सोचने के लिए और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात आज सरकार के लिए है कि काश्मीर को भारत की सीमा के अंदर रखने की। जो परिधि आज हम सारे लोगों ने तय की है, वह भी जिम्मेदाराना बात है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो लोग काश्मीर के सवाल पर एक अलग राय रख रहे हैं जिसकी कि परिणति एकता यात्रा के रूप में हुई थी, उनसे कहना चाहूंगा और खास तौर से सरकार से कि एकता यात्रा अभी तो लोगों के मन में कोई जगह नहीं बना पायी है, लेकिन एकता यात्रा के माध्यम से देश को अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि काश्मीर इस देश की सीमा से अलग-थलग पड़े क्योंकि जन-भावनायें आज कुछ-कुछ अंदर से सुलग रही हैं । महोदय, गृह मंत्री जी शायद लापता हैं । वह अगर यहां होते तो इस बात को नोट करने की कोशिश करते कि आज देश के जन-मानस में ऐसी भावना बन रही है कि जहां देश के लोग यह सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आखिर 45 सालों से कौनसी ऐसी नीति चलायी गयी जिसके तहत आज काश्मीर अलग हो गया । महोदय, कल एक जिक्र हो रहा था इसी सदन के अंदर कि आखिर कितना पैसा इस देश का जम्मू-काश्मीर पर खर्च हुआ । लोग यह सवाल बार-बार पूछ रहे हैं । हमने तो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कीं, सरकार की तरफ से तमाम अनुदान मिले, देश के दूसरे हिस्सों के पैसों को काट-काटकर काश्मीर को दिया गया ताकि काश्मीर के लोगों को यह लगे कि भारत हर हालत में काश्मीर की जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहता है। लेकिन आज वह बात लोगों के दिलों में एक याद बनकर रह गई। जो 1947–48 में हमारा रिश्ता बना था कश्मीर के लोगों से, वह रिश्ता टूट गया। कल भी मैंने कहा था और फिर से दोहरा रहा हूं कि वह इसलिए हो गया कि हमने जिन-जिन नेतृत्वों को कश्मीर में उभारने की कोशिश की, उन्हीं नेतृत्वों को केन्द्र की सरकार के द्वारा बार-बार देशद्रोही कहा गया । क्या वजह थी कि 1953 से 1955, 1955 के बाद 1974–75 का शेख अब्दुल्ला और पार्थ सारथी एकोर्ड और उसके बाद फिर 1977 का चुनाव, फिर फारूख अब्दुल्ला की सरकार फिर फारूख अबदल्ला के खिलाफ, जी.एम. शाह की सरकार ? यह तमाम ऐसी घटनायें घटीं कश्मीर के अन्दर, जिसकी वजह से वहां का नेतृत्व आज ऐसा हो गया है कि काश्मीर में यहां लोग गोली खा रहे हैं, कश्मीर में यहां लोग मर रहे हैं, वहां का नेतृत्व आज कश्मीर से भगा हुआ है । फिर कभी-कभी सुनने में आता है कि उसी नेतृत्व के माध्यम से हम

कश्मीर में स्थायित्व लाना चाहते हैं। कभी यह सुनने में आता है कि जिन लोगों को लंदन की सैर ज्यादा पसंद आई कश्मीर की वादियों के मुकाबले, उनको फिर से कश्मीर का नेता बनाया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि चाहे आप जो तरीका अपनायें, कश्मीर का वर्तमान मौजूदा नेतृत्व, कश्मीर का वर्तमान ढांचा अब मुर्दा बन चुका है। इसमें आप जितनी जान फूंकें, उसमें नई जान आने वाली नहीं है। इसलिए गृह मंत्री जी इस सदन के माध्यम से आप छह महीने के राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक बार इस पर नए सिरे से सोचने का काम करें। दुर्भाग्य से पिछले सात-आठ महीनों में आपकी सरकार ने कोई नई सोच, कोई नई बात नहीं दिखाई। पिछली दफा जब आप राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए सदन में आए थे तो आपने वादा किया था कि छह महीने के अंदर सरकार कोई ऐसी नई दिशा, ऐसी नई ताकत अपनायगी, जिससे कश्मीर का मसला हल हो जाए, मगर मुझे अफसोस है। आप छह महीने के बदले एक साल ले लें कश्मीर के लिए, सदन को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी देने में, मगर आपने कोई तरीका, कोई रास्ता बनाया नहीं और न कोई नई दिशा तय की है। मुझे मालूम नहीं कि इस छह महीने के अंदर, जिसकी अवधि बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, कोई नई दिशा तय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे।

अन्त में, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि कल या परसों, मैंने सुना कि एक कौंसिल की मीटिंग श्रीनगर में बुलाई गई थी। उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार के कौनसे लोग वहां मौजूद थे ? मैं नहीं जानता। लेकिन, जो अखबारों से पढ़ने को, देखने को मिला, उससे ऐसा लगा कि कोई नतीजा नहीं निकला। अगर ऐसे ही मीटिंगों को बुलाकर बिना कोई ठोस सुझाव दिए आप जाने देंगे तो जो कुछ बची हुई संस्थायें इस देश में रह गई हैं, उनसे भी लोगों का विश्वास उठ जायगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार सारे राजनीतिक दलों को, सारे ऐसे लोगों को जिनके पास कोई ठोस सुझाव हों, साथ लें क्योंकि अब वक्त आपके सामने आया है जब आपको कठोर फैसला लेना होगा। अब वक्त ऐसा आया है कि जो फैसला हो वह आखिरी फैसला हो। कश्मीर के बारे में देश अब ज्यादा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। वह उन्माद' कुछ लोगों ने आज कोशिश की है पिछले दिनों भड़काने की, मुझे अफसोस और डर, दोनों इस बात का है कि हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग अलग-थलग पड़ जायेंगे, उन्माद में देश उनके साथ हो जाएगा। इसलिए मैं चेतावनी के साथ आपको कह रहा हूं कि आप एक बार गंभीरता से इस सवाल को सोचते हुए तमाम ऐसे लोगों को इक्कठा करने की कोशिश करो। काम तो कठिन होगा, लेकिन अगर कश्मीर को अपने साथ रखना है, कश्मीर जिसको भारत का अभिन्न हिस्सा मान चुके हैं उसको अगर साथ मिलाकर चलना है तो कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने का काम भारत सरकार और भारत के लोगों को करना होगा तभी उन सपनों को हम पूरा कर पायेंगे, जो सपना कुछ वर्ष पूर्व 1947–48 में गांधी जी ने देखा था। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

डा० अबरार अहमद (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कल शाम जब यहां इसी विषय पर चर्चा चल रही थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सिकन्दर बख्त साहब ने कश्मीर की चर्चा चालू की। बहुत अच्छा होता कि वे आज सदन में होते... (**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं।

डा० अबरार अहमद : अच्छा हुआ, मुझे पता हुआ कि उनके नुमाइंदे बैठे हैं तो मुझे अब अपनी बात कहने में आसानी होगी। उन्होंने कई सवाल खड़े किए और एक सवालों की फेहरिस्त यहां

[डा० अबरार अहमद]

पढ़कर सुनाई। उसमें पहला सवाल उनका था कि कश्मीर क्या है? मुझे हैरत होती है माननीय सदस्य पर कि जिन्होंने यह सवाल पूछा कि कश्मीर क्या है? उन्हें शायद मालूम नहीं कि वह कश्मीर इस हिन्दुस्तान की रुहे-जमीन है, इस हिन्दुस्तान की आत्मा है, भारत माता का सिरमौर मुकुट है, हिन्दुस्तान का दिल है और जब तक चांद और सितारे रहेंगे, वह कश्मीर इस हिन्दुस्तान का अटूट अंग रहेगा। उन्होंने यह सवाल खड़ा किया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सिकन्दर बख्त जी ने आरोप और प्रत्यारोप कांग्रेस पर लगाना चाहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुलाई, 1989 में मैं अपने पूरे परिवार के साथ कश्मीर गया था और उस समय कश्मीर में पूरे तरीके से शांति थी, किसी तरीके से आतंकवाद का डर नहीं था। 1989 के अंदर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने उसका सहयोग किया, उस समय कश्मीर के अंदर एक पापुलर सरकार मौजूद थी। वहां कश्मीर में जब गवर्नर बनाने की बात आई तो वहां के मुख्य मंत्री ने कहा था कि एक आदमी को छोड़कर, जो इस हाउस के माननीय सदस्य हैं, उस एक व्यक्ति को छोड़कर आप किसी को भी गवर्नर बना दीजिए। वहां उस समय जो गवर्नर का फैसला लिया गया तो वहां की सरकार ने जिस आदमी के लिए कहा था कि उस आदमी को छोड़कर के बना दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आकर उस विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उसी व्यक्ति को वहां का गवर्नर बनाया जिसकी वजह से आज कश्मीर के हालात इस हद तक पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी आज अपना दामन छुड़ाना चाहती है, अपना दामन झटकाना चाहती है और कहती है कि कश्मीर के यह हालात कांग्रेस ने बनाए हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब माननीय गवर्नर वहां बनकर पहुंचे, उसके बाद जिस तरीके से वहां अत्याचार, दुराचार और अनाचार, जितने भी प्रकार के थे, वे सब वहां किए गए। वहां के अल्पसंख्यकों को भगाने का निर्णय उन माननीय गवर्नर महोदय ने किया। वहां के अल्पसंख्यकों को भगाने के लिए साधन मुहैया कराए गए और माननीय सिकन्दर बख्त जी कल यह कह रहे थे कि वहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुए, यानी वे यह कहकर हिन्दु और मुस्लिम की बात पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर जो कुछ भी घटा, उसे आप हिन्दु और मुस्लिम के अंदर नहीं बांट सकते हैं। मैं उनकी इस बात को मानता हूं कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं की उसमें पाकिस्तान का हाथ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके अंदर जो आतंकवादी संगठन हैं, वे इस्लामी संगठनों से जुड़ हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां जो भी आतंकवादी संगठन हैं उसमें मुस्लिम लोग सम्मिलित हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जितने लोग मारे गए हों, वह हिन्दू हों। वहां अगर मरने वालों की फहरिस्त आप देखेंगे तो उसमें जितने मुसलमान निकलेंगे उतने ही हिन्दू निकलेंगे। अभी मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1991 के अंदर 382 नागरिक वहां के मारे गए, शायद उनको यह जानकर हैरानी होगी कि उनमें मुसलमानों की अक्सरियत है। तो अगर वह हिन्दू और मुसलमानों की बात कश्मीर में करके, वहां के झगड़े में मुसलमानों की बात करके यह कहना चाहते हैं कि वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुआ है, वहां हिन्दुओं पर जुल्म हुआ है तो वह हिन्दुस्तान के अंदर हिन्दू और मुसलमान के अंदर दरार डालना चाहते हैं, हिन्दू और मुसलमान के नाम पर फसाद खड़ा करना चाहते हैं और उनकी पार्टी की जो जहनियत है, वह सारे हिन्दुस्तान को बताना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह उस वादी के लहू को सारे हिन्दुस्तान के ललाट पर नहीं मसल सकते। सारे हिन्दुस्तान के अंदर वह हिन्दू और मुसलमान की बात करके फसाद खड़ा नहीं कर सकते।

एकता यात्रा की बात उन्होंने बड़े जोरों से कही थी। उपसभाध्यक्ष महोदय, एक यात्रा से उनके हौंसले बड़ थे और

वह यात्रा आडवाणी जी ने निकाली थी। आडवाणी जी की यात्रा और एकता यात्रा के अंदर उददेश्य उनके काफी समान थे, वह जो उद्देश्य लेकर चले थे वह एक थे । लेकिन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया । आडवाणी जी की एकता यात्रा से उन्हें जो राजनीतिक लाभ हुआ था उस लाभ को वह एकता यात्रा से भी लेना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनके उद्देश्यों को पूरा नहीं किया । (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो एकता की बात करते हैं, मैं राजस्थान से ताल्लुक रखता हूं और जयपुर के विश्वविद्यालय में 10 साल प्रोफेसर रहा हूं । आज भी उस जयपुर, गुलाबी नगरी से खून के छींटे मिटे नहीं हैं, जो आडवाणी जी की यात्रा के समय 50 से ज्यादा लोग मरे, जो बच्चों पर जुल्म हुए । एक मां जिसके सीने से बच्चे को अलग नहीं किया जा सका मरने के बाद भी, जो जिन्दा जलाया गया । एक घर के अंदर 7 आदमियों को चाकुओं से नोच-नोचकर मारा गया । यह आडवाणी जी की यात्रा का एक नतीजा था । वह गुलाबी नगरी आज भी उस खून की आग में दहक रही है । उसके बाद उन्होंने साम्प्रदायिकता को धार्मिक आस्था बताकर के जो राजनीतिक लाभ लिया, जो चुनावों के अंदर लाभ लिया वही लाभ ये एकता यात्रा के नाम पर, लेना चाहते थे । उपसभाध्यक्ष महोदय, जब उसके बाद चुनाव हुआ और उन्होंने यह देखा कि इस देश के प्रत्येक आदमी की धार्मिक आस्था बहुत मजबूत है और मैं भी इस बात को मानकर चलता हूं कि यह देश धार्मिक आस्था पर चल रहा है । एक गरीब आदमी जिसको तन ढकने को कपड़ा नहीं है, जिसको एक टाईम ही खाने को रोटियां हैं और उसके सामने एक ऐसा आदमी रहता है जो लम्बी-लम्बी बिल्डिंग में रहता है, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में उसके सामने जाता है । लेकिन वह गरीब आदमी क्या सब्र करता है ? वह सब्र करता है कि जिस दिन मेरा भगवान मेरी किस्मत बदलेगा, मेरा अल्लाह मेरी किस्मत नवाजेगा तो मैं इससे भी बड़ी गाड़ी में जाऊंगा, मैं इससे भी बड़े मकान के अन्दर रहूंगा और जिस दिन वह इसकी किस्मत को बिगाड़ेगा यह मुझसे भी बदतर हालत में होगा । अगर आदमी सच बोलता है तो अपनी धार्मिक किताब के डर से या किसी कानून के डर से नहीं, अगर अनुशासन में रहता है तो वह इस बात से डरकर कि वह नीली छतरी वाला मेरे को देख रहा है । अगर वह ईमानदारी बरतता है तो इस बात से डरकर कि वह भगवान मेरे को देख रहा है । तो जब इन्होंने यह देखा कि आदमी की धार्मिक आस्था इतनी मजबूत है कि अगर उससे उसका कुरान छीन लिया जाये, उसकी गीता छीन ली जाये, उसकी बाईबिल छीन ली जाये, उससे उसका गुरु ग्रंथ साहिब छीन लिया जाये तो वह इंसान जिन्दा नहीं रह सकता । तो जब इन्होंने इस बात को देखा कि धार्मिक आस्था इतनी मजबूत है तो उन्होंने साम्प्रदायिकता को धार्मिक आस्था के नाम से प्रचारित किया । साम्प्रदायिकता को धार्मिक आस्था का जामा पहनाया । साम्प्रदायिकता क्या है ? आदमी अपने धर्म को तो माने लेकिन दूसरे के धर्म से नफरत करे, दूसरे के धर्म को नेस्तनाबूद करने के लिये सर्वस्व न्योछावर कर दे। तो उन्होंने उस साम्प्रदायिकता को धर्म के नाम पर अनपढ़ लोगों में, गरीब लोगों के अन्दर प्रचारित किया और जिसके नतीजे में इनको चुनाव के अन्दर कुछ सीटें ज्यादा मिलीं और उससे प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर इन्होंने एकता यात्रा का एक नया नाटक खड़ा किया । उस एकता यात्रा के भी वही उददेश्य थे जो अडवाणी जी की रथ यात्रा के थे । लेकिन उनके वह उद्देश्य पूरे नहीं हो सके, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने उनकी इस यात्रा को कहीं रोका नहीं, जिससे वे हीरों बन सकें, जिससे वे खून की होली खेल सकें ।

कल बड़ जोरों से कह रहे थे कि उस लाल चौक पर हमने झंडा फहराया। मैं पूछना चाहता हूं कि तिरंगा झंडा तो यह कांग्रस सरकार और इस कांग्रेस के द्वारा कश्मीर के लिये बनी हुई सरकार हमेशा फहराती रही है और उस दिन भी जो झंडा फहरा वह प्रधान मंत्री जी ने

[डा० अबरार अहमद]

ही इनके हाथों से वहां फहरवाया, वरना वहां जाने की इनकी हिम्मत नहीं थी। क्योंकि 15 अगस्त, 26 जनवरी को कोई भी नागरिक कहीं भी तिरंगा झंडा फहराने का अधिकारी है और अगर उसके अंदर कोई विवशता है, कोई दिक्कत है तो सरकार का कर्तव्य है कि उसको सुविधा उपलब्ध कराये। तो वे जिस तिरंगे झंडे की बात करते हैं, हमारे प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी ने वायुयान से उन्हें वहां पहुंचवाया और तिरंगा झंडा फरवाया, वरना इनकी क्या हैसियत थी और क्या बिसात थी कि वे वहां तक पहुंच सकते थ, जिसके बारे में इतने फक्र की और गर्व की बात करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कल सिकन्दर बख्त साहब ने जमाते इस्लामी की एक बात यहां कही थी। जमाते इस्लामी वास्तव में एक धार्मिक संगठन है। वे यहां नहीं हैं, वरना मैं उनको यह बताता। उनके प्रतिनिधि इस बात को अवश्य सुन रहे होंगे कि कांग्रेस का कभी इस जमाते इस्लामी से सम्बन्ध नहीं रहा। लेकिन 1977 के अंदर अगर किसी एक मंच से भाषण दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जमाते इस्लामी के नेताओं ने दिया। अगर चुनाव एक साथ लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जमाते इस्लामी के नेता एक जगह लड़े। जिसका कांग्रेस पर यह आरोप लगाना चाहते हैं। जब उनका मतलब होता है, स्वार्थ सिद्धि होती है, और वोटों की राजनीति में कोई मदद करता है तो वही जमाते इस्लामी उनकी सहयोगी हो जाती है, उनके लिये अच्छी हो जाती है। लेकिन जब उनका स्वार्थ नहीं रहता तो उसको कांग्रेस पार्टी पर या जिस भी पार्टी का राज्य है, उसको लांछित करने के लिये जमाते इस्लामी की उंगली उसकी तरफ उठाने का वह प्रयास करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य हरि सिंह जी जब यहां अपनी बात कह रहे थे तो एक बड़ा अच्छा सुझाव उन्होंने दिया था और मैं भी उस सुझाव की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि विदेशी दूतावासों के अन्दर नौकर-पेशा लोगों को कम भेजा जाये, राजनीतिक लोगों को ज्यादा भेजा जाये। इसकी वास्तव में एक अहमियत है। जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं या जितने भी दूसरे देश हैं वहां उनका राजा या बादशाह या प्रधान मंत्री एक नौकर पेशा आदमी को बराबरी का दर्जा नहीं देता, उससे भी बात करना पसंद नहीं करता उससे भी राजनीतिक बातों के अंदर आपस में बराबरी के दर्जे की बात को नहीं लेता। लेकिन अगर राजनीतिक व्यक्ति को हम वहां लाते हैं, राजनीतिक

3 P.M. व्यक्ति को हम वहां भेजते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश के जो राजनीतिक उद्देश्य हैं, वह उसके द्वारा पूरे हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो भी एक व्यक्ति अपनी सर्विस के दृष्टिकोण से विदेश जाना चाहता है, उसकी प्राथमिकता में और एक राजनीतिक व्यक्ति की प्राथमिकता में फर्क पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति मात्र नौकरी के लिए विदेश में जाएगा तो उसकी प्राथमिकता अपने स्वयं और अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने की होगी और एक हद तक एक समय सीमा के अंदर 10 से 5 बजे तक की नौकरी करने की होगी और उसके बाद प्राथमिकताएं दूसरी होंगी। लेकिन अगर एक राजनीतिक आदमी वहां जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी प्राथमिकता अपने देश के लिए होगी और उसका जो उद्देश्य है वहां रहने का, वह उसे पूरा करेगा। इसलिए जहां तक दूतावासों के अंदर राजनीतिक उद्देश्य के लिए नियुक्तियों की बात है, उसमें राजनीतिक लोगों को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाए।

महोदय, मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इस कश्मीर समस्या से निपटने के लिए जिस मजबूत के साथ नरसिंहराव जी की सरकार प्रयास कर रही है, जिस मजबूती के साथ इस समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं, उससे मैं यकीनी तौर से कह सकता हूं कि कुछ ही दिनों के अंदर यह समस्या समाप्त हो जाएगी।

अभी जिस प्रकार से जे.के. एल.एफ. पर पाबंदी लगाई गई, वह बहुत जरूरी था क्योंकि उस संगठन के माध्यम से आतंकवादी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे थे। उसके माध्यम से वे निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे थे और आतंक पैदा कर रहे थे। उससे यह बहुत जरूरी हो गया था कि इस तरह के संगठनों पर पाबंदी लगाई जाए और वह कार्य हमारी सरकार ने किया।

इसके साथ ही साथ एक तीन सूत्री प्रोग्राम दिया गया है और उसके तहत आतंकवादियों पर बराबर दबाव डाले रखना, आतंकवादियों के विरुद्ध सूचनाएं प्राप्त करना और सुरक्षा बलों को कम से कम क्षति पहुंचे, इस तीन सूत्री कार्यक्रम के तहत वहां पर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि आतंकवादियों की शक्ति कम हो और वहां शांति स्थापित हो।

इसके साथ ही साथ में आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर की स्थिति के सुधार के लिए कुछ आवश्यक बातें जो सरकार को करनी चाहिए और जिनके बारे में मेरे पूर्व वक्ता साथियों ने भी कहा है कि वहां रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराया जाए जिससे जो बेरोजगार युवा भटक जाते हैं या पाकिस्तान जो हमेशा इस प्रयास में लगा रहता है कि किसी प्रकार से हमारे मुल्क के अंदर अस्थिरता पैदा हो और यहां के युवाओं को भटकाकर यहां-वहां ले जाकर ट्रेनिंग दी जाए, उनको यदि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो शायद उसके उस कार्य में निश्चित रूप से बाधा पहुंचेगी। दूसरा, वहां के लोगों में कान्फिडेंस रिस्टोर किया जाए और तीसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से बख्त साहब के प्रतिनिधियों से मैं कहना चाहूंगा कि वे कश्मीर के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, शांति चाहते हैं लेकिन हर बार ये नारा लगाते हैं और यह बात कहते हैं कि धारा 370 हटा दी जाए तो इसको हटाने की बात कहकर वे वहां शांति स्थापित करने की बात करते हैं या वहां के लोगों में इस प्रकार की भावनाएं पैदा करते हैं कि ये हमारे अधिकारों को कचोटना चाहते हैं।

अगर वे वास्तव में वहां शांति चाहते हैं तो पहले वहां के माहौल को सामान्य बनाने के लिए यह नारा लगाना छोड़ें, 370 की बात छोड़ें। जब वहां की स्थिति सामान्य हो जाएगी, सारी बातें ठीक हो जाएंगी तो हो सकता है कि एक दिन वह भी आए जब 370 हटा दी जाए लेकिन अभी के माहौल में जब कश्मीर में आग लगी हुई हो, जब पाकिस्तान कश्मीर के माध्यम से हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करता हो, वहां इस आग के अंदर तेल डालें और धारा 370 को हटाने की बात करें ताकि वहां के लोग भी उस बात को सुनकर भड़कें और पाकिस्तान जो करना चाहता है, उसको अपने मकसद में कामयाबी मिले तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी वे धारा 370 की बात को बिल्कुल खत्म करें, उसकी बात न करें और उस दिन का इंतजार करें जब सारी स्थिति सामान्य हो जाए और वहां के लोग कहें कि आज हम में और देश के दूसरे हिस्सों में कोई फर्क नहीं है इसलिए यह धारा हटनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कश्मीर के लोगों से पाकिस्तान को कोई सिम्पैथी नहीं है। वह सिर्फ कश्मीर के लोगों को एक टूल बनाकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है। इस बात को लोगों को समझाने की जरूरत है। जो लोग कश्मीर से शरणार्थी के रूप में यहां आए हैं, चाहे वे किसी भी कारण से आ गए हों, किसी भी धर्म या समुदाय के हों, उनकी पूरी मदद की जानी चाहिए और उनको दोबारा वहां भेज करके उनकी पुनर्स्थापना की व्यवस्था की जानी चाहिए।

महोदय, अंतिम बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे पूर्व वक्ता कल दूरदर्शन की बात यहां कह रहे थे कि दूरदर्शन पर जिस प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं कश्मीर के अंदर, जो पाकिस्तान के

[डा० अबरार अहमद]

प्रोग्राम है, वे काफी लोकप्रिय होते हैं। काफी अच्छे नाटक या अन्य प्रोग्राम वहां दिखाए जाते हैं लेकिन हमारे दूरदर्शन द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं दिखाए जाते हैं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वास्तव में सवाल अच्छे नाटक या अन्य कार्यक्रमों का नहीं है बल्कि उन नाटकों और संगीत के कार्यक्रमों के माध्यम से वहां की जनता को गुमराह किया जाता है चार घंटे तो वे नाटक दिखाते हैं या संगीत दिखाते हैं तो आधा घंटा वे लोगों को भड़काने वाली बात करके हमारे देश के लोगों को उकसाते हैं। इस को देखते हुए आपको चाहिए कि दूरदर्शन के ज्यादा से ज्यादा केन्द्र वहां पर बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन कार्यक्रमों को देख सकें और सही बात को समझ सकें और नाटकों के जाल में फंसकर जो वे चार घंटे में से आधा घंटा इस देश के लोगों को भड़काने वाली बातें कहकर अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं उनको अपने मकसद में नाकामयाबी मिले। इसलिए मेरा अंतिम सुझाव होगा, इस मंत्रालय की माननीया मंत्री महोदया, यहां बैठी हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि व इस संबंध में कार्यवाही करेंगी जिससे पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब न हो सके और इस देश के लोगों को गुमराह न कर सके। धन्यवाद।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके पहले जब 6 महीने के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की बात आती थी तो हमारे जैसा आदमी सोचता था कि 6 साल में भी काश्मीर का सवाल हल हो जाए तो हम देखकर मरेंगे...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : मरने की बात क्यों करते हैं, अभी आप दीर्घायु होंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : राजनीतिक दृष्टि से।...

श्री चतुरानन मिश्र : राजनीतिक नहीं शारीरिक दृष्टि से। हमने कहा कि हम ऐसा सोच रहे थे कि 6 साल में भी वहां की हालत ठीक होगी या नहीं। अब एक फेवरेबल फैक्टर हो गया, कोल्ड-वार अब समाप्त हो गया है। इसके बाद एक नई संभावना जगी है, मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार इस बारे में सचेष्ट है या नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दुनियां में एक ऐसा वातावरण आया है जिसके चलते पाकिस्तान को पहले जैसे अमरीका से मदद मिल रही थी वह मदद अब संभव नहीं है। जे.के.एल.एफ. के मूवमेंट में भी हमने देखा कि इस तरह की बात हुई है। यह परिवर्तन आया है। आपने यह भी देखा कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने दूसरा रुख अपनाया है। उनको भी कहना पड़ा कि शिमला पैक्ट के अदर बातचीत होनी चाहिए। जो यूरोप के अन्य देश हैं उनके भी विचार में परिवर्तन आया है। इसमें दो तीन फैक्टर हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए।

पहला यह है कि सारी दुनियां में टैरोरिज्म को एक गंभीर समस्या समझकर उसके खिलाफ एक वातावरण बना है। दूसरा सबसे बड़ा मसला यह है कि नशीले पदार्थों का जो व्यापार होता है उससे बहुत ज्यादा पैसा आने से उग्रवाद को बढ़ावा मिला है। तीसरी बात यह है कि लोग रीजनल वार नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे हालत खराब होने लगती है। मेरा ख्याल है कि हमारी सरकार इन तीनों मुद्दों का जो उपयोग करना चाहिए वह नहीं कर रही है। एक मुद्दे का इन्होंने इस्तेमाल किया। जब हमारी सरकार ने यू.एन.ओ. को पत्र भेजा जे.के.एल.एफ. के बारे में तो हमारे जैसे आदमी को चिन्ता हुई कि कहीं दूसरे वक्त पर इसका नाजायज इस्तेमाल तो नहीं होगा क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री गए थे सैक्यूरिटी काउंसिल के 15 जो सदस्य हैं उनकी सरकारों के हैड्स की बैठक में। उसमें एक क्लाज बड़ा खतरनाक है। अभी तो समझ में नहीं आ सकता है। उसमें है कि सैक्यूरिटी काउंसिल प्रिवेंटिव ऐक्शन ले सकती है। यह प्रिवेंटिव ऐक्शन लेने का अधिकार

दे दिया जाए तो न जाने कहां पर प्रिवेंटिव ऐक्शन ले लेंगे, इसका मुझे भय है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की सम्गलिंग का जो धंधा है वह रुकने से काम नहीं चलेगा क्योंकि उसमें पाकिस्तान ही नहीं, भारत की भूमि का भी इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं सरकार किन कारणों से जितनी संजीदगी से काम लेना चाहिए था वह नहीं ले रही है। यह जो व्यापार है यह बिलियन डालर्स का है। नाजायज रूप से कमाकर वह टेरेरिस्टों को देते हैं। मर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसा आर्मी में होता है। इसलिए मैंने इन तीन बिन्दुओं की चर्चा कि इन पर बड़ी सावधानी से काम होना चाहिए तब हम देखेंगे कि काश्मीर समस्या का समाधान हो पायेगा।

दूसरे, दूसरे माननीय सदस्यों ने पाकस्तिान के बारे में कहा। मैं उससे सहमत हूं कि पाकिस्तान बहुत खुराफात करवा रहा है। इससे मैं अपने भाई सिकन्दर बख्त जी से भी सहमत हूं। जिस बात पर उनसे सहमत नहीं हूं वह बहुत गम्भीर बात है और यह हमारे दिमाग में है। आप प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं इस पर जरा सोचिए। सब मिलकर सोचिए जो हम रख रहे हैं। क्या वजह है दुनियां का यह भूभाग जो ओलडेस्ट सिविलाइजेशन आफ लैंड रहा है, मेसोपोटामिया, बेबिलमेन मिश्र, अल्जीरया, ग्रीस और दूसरी तरफ चले आइये, भारत, श्रीलंका के अंदर हम देखते हैं कि एक रिलीजस फंडामेंटेलिज्म है। हमारे भाई सिकन्दर बख्त ने बड़ी चर्चा की कि मुसलमानों में इस तरह का फंडामेंटेलिज्म है। वह हैं नहीं, हमारे दूसरे भाई लोग हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यहां के हिन्दुओं को क्या हो गया यह तो मुसलमान नहीं है। यह भारत के हिन्दू मुसलमान नहीं है इनको क्या होगया। यह सवाल कहां से उठाकर ले आये। बाबरी मस्जिद और अयोध्या की बात इतने दिनों तक नहीं उठी आज क्यों उठ गई? इतिहास के 500 वर्ष की बात उठाकर ले आये क्योंकि यह आपकी राजनीति को सूट करती थी। यह दूसरे को दोष देकर नहीं होगा। अगर आप कहें श्रीराम के भक्त आप बहुत ज्यादा है तो मैं आपसे कहूंगा कि तुलसीदास भी आप से कम भक्त नहीं थे। उन्होंने इतनी मोटी रामायण लिखी। उसमें उन्होंने कहीं भी लिखा बाबरी मस्जिद का सवाल हल करना चाहिए। एक लाइन लिख देते तो कोई हर्ज नहीं था। किसी का डर नहीं था उनको।

उपसभाध्यक्ष (श्री चन्द्रेश पी० ठाकुर): तुलसीदास जी हिस्टोरियन नहीं थे।

श्री चतुरानन मिश्र: हिस्टोरियन की बात नहीं है। उधर से जो लोग आ रहे हैं क्या सब हिस्टोरियन ही आ रहे हैं। इसलिए यह मत कहिये ये हिस्टोरियन लोग ऐसा कह रहे हैं। लिखते तो चेतना होती अनैतिक बात होती तो महराणा प्रताप इस सवाल को लेकर उठ गये होते। थोड़े दिन के बाद बाबर के पौते के वक्त में यह हुआ था वह इस सवाल को उठा लेते जो आज उठाया जा रहा है। इसमें कुछ गलत बयानबाजी घनघोर प्रचार अखबारों में होता है। जो हमारे जम्मू-कश्मीर के गवर्नर हैं उनको पत्र लिखा। क्योंकि मैं दो महीने पहले वहां गया था इसलिए कि वहां के हिन्दुओं ने शिकायत की थी कि हमारे बहुत से मन्दिरों को तोड़ दिया गया। मैंने वहां के गवर्नर को पत्र लिखा कि यह बताया जाए कितने हिन्दु मन्दिरों को तोड़ा गया और नाम लिखकर पूछा कि क्या ये ये मन्दिर तोड़े गये? गवर्नर के जवाब को मैंने राष्ट्रीय एकता परिषद में भी पेश किया था। उसमें बताया गया कि मात्र दो मन्दिरों को तोड़ा गया और एक डैमेज हुआ है। एक मस्जिद भी डेमेज हुई है और यह आतंकवादियों ने की है। लेकिन भाजपा अखबार लिखते हैं कि दर्जनों, सैकड़ों तोड़े गये यह उन्माद पैदा करने के लिए लिखते हैं। कोई इनसे पूछे आपकी यह जो रथ यात्रा शुरू हुई एकता यात्रा के पहले जिसको दंगा यात्रा कहते हैं उस वक्त कितने मस्जिदों पर हमला हुआ भारत में? इसका कोई जवाब देंगे? अगर किसी निष्पक्ष अदालत में जायेंगे तो क्या जवाब दिया जायेगा, ?पता नहीं। जो भारत में

[श्री चतुरानन मिश्र]

हिन्दु-मुस्लिम दंगे हुए हैं सिर्फ 1988-89 में, इन दो वर्षों में जो मेजर दंगे हुए हैं उसमें 2,129 व्यक्तियों की मत्यु हुई और 4,899 लोग बुरी तरह से घायल हुए इस पुण्य भारत भूमि में। इसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं ?

श्री संघ प्रिय गौतम : आपने 1989 के दंगों का जिक्र किया तो तब न रथ यात्रा निकली थी और न एकता यात्रा निकली थी ।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने कहा सिर्फ दो साल का । दुनियां के लोगों को आप क्या जवाब देंगे ?

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : वहां पर सिर्फ एक ही जाति के लोग नहीं मरे हैं, बल्कि सभी जातियों के लोग मरे हैं, आप सिर्फ एक की ही बात करते हैं... (व्यवधान) ।

श्री चतुरानन मिश्र : हम यह बात कहां कह रहे हैं ? आपके मन में चोर है, इसलिये आप यह बात कह रहे हैं। हमने तो कहा है कि दोनों भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग मरे हैं। जब धर्म युद्ध होता है तो आपका नाम युद्ध करवाने वालों में होता है। यही बात वे लोग भी कहते हैं..(व्यवधान)। इसका मतलब तो यह हुआ कि ये सब लोग गलत हैं, आप ही ठीक हैं। आप ही बताइये कि दंगा-फसाद वहां पर क्यों होता है जहां जहां पर आप जाते हैं ? यही आप बता दीजिये। हम इसलिए इन बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इस बारे में आपकी पार्टी का और हमारा मतभेद है। यह समस्या नहीं हैं। समस्या यह है कि काश्मीर एक ऐसा भूभाग है जो पाकिस्तान से सदा हुआ है। यह बंगाल और बिहार की तरह से नहीं है। वहां के लोग मुख्यतः गांधी जी और नेहरू जी को देख कर भारत के साथ आये थे। मैं भी कश्मीर गया था। वहां के मुसलमानों ने हमसे कहा कि वे सेकुलर भारत के साथ आए थे। उनके साथ नहीं आये हैं जो दंगा करवाने वाले हैं। कांग्रेस सरकार यहां पर बैठी हुई है। आप मुरली मनोहर जोशी को हवाई जहाज से ले जाइये, राकेट से ले जाइये, यह आपकी खुशी है। लेकिन वहां के लोग समझ रहे हैं कि आप उनको संरक्षण दे रहे हैं जो भारत में हिन्दूवाद को जगा रहे हैं। आपका यह राजनैतिक दांवपेंच हो सकता है। लेकिन आप यह समझ लीजिये कि आप दुनिया के पास यह संदेशा दे रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ कम्प्रोमाइज कर रहे हैं जिनका नाम भारत में दंगा-फसाद कराने वालों में है। हम इसकी चर्चा क्यों करते हैं ? इसलिए नहीं कि हम बी.जे.पी. पर कोई हमला करना चाहते हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि भारत में जो सेक्यूलरिज्म है उसके ठीक विपरीत आप प्रचार कर रहे हैं। इसलिये कश्मीरी लोग भड़क जाते हैं। आप जानते हैं कि उनके नजदीक पाकिस्तान है और पाकिस्तान उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। मैं सिर्फ एक ही मुद्दे पर बोलना चाहता हूं, और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पो० ठाकुर) : आप समय बहुत ले चुके हैं। आप विषय पर बोलिये।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप इनको बोलने दीजिये, हम भी सुनना चाहते हैं ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : आलोचना कर रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि समस्या का निदान तब तक नहीं होगा जब तक आप फिर से गांधी और नेहरू के रास्ते पर चलकर भारत का सेक्युलेरिज्म का झण्डा बुलन्द नहीं करेंगे। तब तक लोग आपके साथ नहीं आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के आप माननीय सदस्य वहां गये थे या नहीं गये थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन श्रीनगर के आपके साथ पांच आदमी भी नहीं थे।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था।

श्री चतुरानन मिश्र : कर्फ्यू लगा होता है तो क्या लोग नहीं आते हैं ? हम स्वयं कर्फ्यू तोड़कर जाते हैं। आप

कर्फ्यू हटा दीजिये, फिर देखिये आपके साथ कितने आदमी आते हैं। आपको तो दुबई जहाज मिला हुआ था, पब्लिक की तरफ से तो आपको जीरो मिला हुआ था। इसलिए सेन्ट्रल क्वेश्चन यह है कि एजिटेशन आफ दी पीपुल आफ काश्मीर क्यों हुआ? जो कश्मीरी लोग पाकिस्तान से लड़े थे, जिन्होंने अपना खून बहाया था, वे आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने काश्मीर में खून नहीं बहाया था। नेहरू जी की फौज वहां नहीं पहुंची थी। उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान का मुकाबला किया था। लेकिन ऐसी कुछ घटना घटी है जिसके चलते यह बात हुई है। मैं यह बात एक राजनैतिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं। प्रशासनिक ढांचे पर तो बहुत से लोग बोले हैं और आपको जो कार्यवाही करनी चाहिए वह अवश्य कीजिये, सेक्यूरिटी का प्रबन्ध कीजिये। लेकिन दिल को जोड़ने का काम राजनैतिक पार्टियों को करना है। इसमें आपकी पार्टी बाधा डाल रही है। आप चलिये काश्मीर में और मीटिंग कीजिये। आपकी मीटिंग में सियार भी नहीं भोंकेगा... (व्यवधान)।

श्री संत प्रिय गौतम: आप ही वहां पर सरकार बना लीजिये या ये बना लें।

श्री चतुरानन मिश्र: मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप सरकार की सोच रहे हैं? आप तो सरकार की बात सोचते हैं, हम देश की बात सोचते हैं। यही आप में और हम में फर्क है। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, यू.पी. में है तो क्या आप हमारी गर्दन काट लीजियेगा। लेकिन जो हमारी गर्दन काटेगा हम उसकी गर्दन पहले मरोड़ कर फेंक देंगे।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): हिंसा की चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र: अगर कोई हमारी गर्दन काटेगा तो हम उसकी गर्दन मरोड़ कर पहले ही फेंक देंगे। इसलिए ऐसी बात मत कहिये, आपकी गर्दन भी बची रहेगी और हमारी भी बची रहेगी। तो इसलिये हम जिस बात की जिक्र कर रहे थे उपसभाध्यक्ष महोदय कि जनता को जीतने के लिये सरकार हम लोगों की कुछ मदद करे। पहली बात यह है कि जो भी सेकुलर पार्टीज हैं, उन पार्टीज की प्रधानमंत्री एक मीटिंग बुलायें और जिसमें नेशनल कान्फ्रेंस के लोग भी रहें और एक रास्ता इसमें तय किया जाय कि हम लोग जनता का हृदय जीतने के लिये वहां क्या क्या करें। उपसभाध्यक्ष महोदय, उसमें एक प्वाइंट है, जो कश्मीर का भारत में विलय हुआ है उसका एक इतिहास है। हमारे पास वक्त नहीं है जो कि इसके इतिहास में जाएं लेकिन आर्टिकल 370 इज ए नेशनल कमिटमेंट। आप अभी इसके खिलाफ मत जाइये। हमारा ख्याल है कि वह वक्त आयेगा जब कि वही लोग कहेंगे कि वह परिवर्तन चाहते हैं। आप मत कहिये कि हम इसको तोड़ेंगे क्योंकि यह एक नेशनल कमिटमेंट है। आप वहां उचित ढंग से लोगों को सेक्यूरिटी दीजिये। वहां पर हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी को मार दिया गया, कई लोग मारे गये हैं। कोई राजनीतिक पार्टी दफ्तर नहीं चला सकती वहां पर कुछ एरियाज हैं जो मिलिटेंट की दृष्टि से बड़े कमजोर इलाके हैं। वहां हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सरकार के लोग वहां से भाग गये हैं। आपका टी.वी. वहां नहीं जाता, रेडियो नहीं जाता, सब दफ्तर जम्मू में पड़े हुए हैं। सभी पार्टियों के लोग भागकर जम्मू में पड़े हुए हैं। कहीं तो प्रोटेक्शन दीजिये ताकि हम लोग वहां काम कर सकें, पर्चे बांट सकें और उनसे कुछ बात कर सकें कि क्यों तुम हमसे नाराज हो, क्या ऐसी बात हुई है, कहां जाना चाहते हो। मैं समझता हूं कि यह जो परिस्थिति आई है, जिसका मैंने पहले ही आपको बताया कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते नये हालात पैदा हुए हैं और हम चाहते हैं कि भारत की तमाम राजनैतिक पार्टियां इसका हल निकालने की कोशिश करें। इसी संबंध में, मैं रिफ्यूजियों के बारे में कई बार बोल चुका हूं और मैं फिर इसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि वे एक अमानवीय स्थिति में पड़े हुए हैं। इसलिये हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार उनके बारे में सोचे।

[श्री चतुरानन मिश्र]

दूसरी बात यह है कि जो लोग जेलों में हैं उनको कितने दिनों तक बिना मुकदमा चलाये आप वहां रखेंगे, एक साल, 6 महीने । इसलिये आप ऐसे लोगों को छोड़ दीजिये ताकि वे जल्दी से जल्दी बाहर आयें और आप उनके साथ बातचीत कर सकें ।

भारत की सीमा पर जे.के.एल.एफ. के एक सेक्शन में बहुत बड़ा हंगामा मचाया हुआ है, । लेकिन आप जानते हैं कि वह एक दूसरा सेक्शन है जोकि इतना फंडामेंटलिस्ट नहीं है, इतना रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट नहीं है जितना कि जमायती-इस्लाम का मिलिटेंट सेक्शन है। मैं चाहता हूं कि एक डिफेंशियल अप्रोच आप उनके बारे में लीजिये और उनके साथ बातचीत चलाइये । इस बारे में कुछ हम लोगों को भी सुविधा दीजिये ताकि हम लोग इस बारे में उनके साथ बातचीत कर सकें । लेकिन अभी आपकी कोई लाइन नहीं है। भाजपा का लाइन आफ आपरेशन है वहां मिलेट्री भेज दो । अगर मिलेट्री ही भेजना है तो आप और हम लोग क्यों बैठे हुए हैं ? जो रास्ता आप बता रहे हैं तो उसके चलते आज यह दिन आ गया कि कश्मीर में मिलेट्री भेज दो, पंजाब में मिलेट्री भेज दो, यू. पी. की तराई में मिलेट्री भेज दो और मध्य प्रदेश में बाहर से नई नई बंदूक लाने की इजाजत दे दो और फिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो आंध्र में मिलेट्री भेज दो, सारी जगह मिलेट्री भेज दो और हम सब लोग लोटा डोरी लेकर कहीं दूसरी जगह चले जायें । यह कोई रास्ता नहीं है डेमोक्रेसी का । जो डेमोक्रेसी का रास्ता है उसको अपनाकर ही हमको इस समस्या का हल करना चाहिये ।

महोदय, मैं एक दो मिनट का समय और लेना चाहूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चंद्रेश पी० ठाकुर): आधा मिनट लीजिये । बहुत समय आपने ले लिया है ।

श्री चतुरानन मिश्र: अभी हमारे एक मित्र ने यूनिफार्म सिविल कोड की बात कही । हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम इस बात के बिलीवर हैं कि यूनिफार्म सिविल कोड होना चाहिये लेकिन यह स्वेच्छा से होना चाहिये, जबर्दस्ती किसी पर लादकर नहीं होना चाहिये । ऐसी बात है कि उनकी जो रिलीजियश बुक है, इस्लाम के मानने वालों की, उसमें बहुत डिटेल में हिदायतें हैं पर्सनल ला के बारे में । ऐसा गीता में नहीं है, वेदों में नहीं है । हमारे वेदों में सिर्फ प्रेयर्स है । लेकिन उसमें ऐसा है कि लड़की को कितना हिस्सा मिले, लड़के को कितना हिस्सा मिले, शादी किसके साथ हो और किसके साथ न हो, ये सारी डिटेल्स पैगम्बर साहब की हिदायतों में है । लेकिन भाजपा के साथियों के कहने का अर्थ कि कुरान शरीफ में तरमीम कर दिया जाये, उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाय, तो क्या यह कोई रेजोल्यूशन है जो पास हो रहा है और आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं । इसलिये हम लोग कहते हैं कि इस दिशा में हम लोग कार्य करें, प्रचार करें और उनको इन बातों को समझायें कि देश के अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: आप यह मानते हैं न कि यूनिफार्म सिविल कोड होना चाहिये ?

श्री चतुरानन मिश्र: होना चाहिये लेकिन जबदस्ती नहीं बल्कि स्वेच्छा से होना चाहिये । यही हमारे और आपमें फर्क है। हमारा बहुत साफ स्टैंड है, यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है । यूनीफार्म सिविल कोड कोई नयी बात नहीं हो रही है । हमारे संविधान के अनुसार हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिये लेकिन विलिगनेस के आधार पर, कम्पलशन के आधार पर नहीं, रिलीजियस इंटरफियरेंस कर के नहीं । इसके लिए आप काम कीजिये। इसलिए हम बी.जे.पी. के मित्रों से यह कहेंगे कि सचमुच में आप इस दिशा में कुछ काम करें और उनके हृदय को जीतने का प्रयास करें । मैं समझता हूं 6 मास की नहीं 9 मास की अनुमति हम दे देते

है लेकिन आपसे डिलीवरी नहीं होती है। यही दिक्कत है, 9 महीने भी अगर ले लें, इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कोई ऐसी लाइन आप तय कीजिये, लाइन आफ एक्शन, एक्शन प्लान हो जिसमें हम सब लोग मिल करके उनके पास जाएं और उनके हृदय को जीत सकें और कश्मीर की समस्या हल कर सकें। मैं यह आपको बता रहा हूं कि कश्मीर में विदेशी हस्तक्षेप अब दिनोंदिन घटेगा। इसलिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये जिससे हम निकट भविष्य में वहां चुनाव करवा सकें और बार बार राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत न रहे। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Shri Mohd. Khaleelur Rehman. One request to hon. Members. We have limited time. Today, this Statutory Resolution has to be passed. There is no time. The deadline is 2nd March. We expect the Finance Minister here any time. He may have some communication.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : Sir, we are not meeting on 2nd march.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Yes. We are not meeting on 2nd March. Therefore, in view of the limitation of time, I hope hon. Members will appreciate it and co-operate.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Uttar Pradesh) : Are we taking up the Motion of Thanks on the President's Address today?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Not today. It is not listed for today.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : It is listed.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : May be, if we have time, we can make a beginning. Now, Mr. Rahman. Don't take more than five minutes.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : मेरी पार्टी का टाइम कितना है?

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर:) : इतना सारा अनुरोध इसीलिए तो किया गया है कि आप वालेंटरी इसमें कुछ सहयोग कीजिये।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : कोशिश करेंगे, कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : जनाब वाइसचेयरमैन साहब, कश्मीर का मसला बड़ा हसास मसला है लिहाजा इस मसले को इंतेहाई एतिहात के साथ निबटने की जरूरत है और डील करने की जरूरत है। 1947 ईस्वी में जब कश्मीर का इलहा हिन्दुस्तान से हुआ था अभी जैसे कहा गया मिश्रा साहब की जानिब से कि हिन्दुस्तान सेकुलर मुल्क है लिहाजा हमको सेकुलर मुल्क के साथ रहना चाहिये, यह समझ कर कश्मीर के आवाम ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कयादत में कश्मीर का इलहा हिन्दुस्तान के साथ किया था। मगर इंतेहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन पिछले 40–42 सालों में जिस तरह से कश्मीर के मसले को डील किया गया इफ्तदा से और इफ्तदा 1953 से शुरू होती है जब कि उसी शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसकी कयादत में कश्मीर का इलहा हिन्दुस्तान के साथ

[श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान]

हुआ था । शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर के कोशिश इस बात की गई कि बख्शी गुलाम मोहम्मद जैसे कठ-पुतली वजीरे आला को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए । कई साल तक बख्शी गुलाम मोहम्मद की हकूमत चलती रही । मगर फिर यह महसूस किया गया कि इक्तदार फिर दोबारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हवाले किया जाए इस वजह से कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही एक वाहेद लीडर थे तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम के जोकि उनके आइनादार थे और वहां के मजहर थे । चुनांचे यह समझ कर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दोबारा चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया गया । फिर इसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद फारूख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया गया । फारुख अब्दुल्ला के ताल्लुक से भी यह देखा गया कि फारुख अब्दुल्ला के साथ भी ज्यादती की गई और जी०एम० शाह को कुछ दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया गया । लिहाजा वाकयात यह जाहिर करते हैं कि जिस तरह से कश्मीर के मसले को डील करना चाहिये था उस तरीके और एति-हात के साथ कश्मीर के मसले को डील नहीं किया गया ।

फिर इस दौरान में कई इलेक्शन वहां पर कराये गये जैसे कि कल ही मेरे मोहतरम बुजर्ग सिकन्दर बख्त साहब ने कहा था । मैं उनकी बात से इत्तिफाक करता हूं इस हद तक कि जितने भी इलेक्शंस वहां पर कराये गये, सही मानों में वे इलेक्शन नहीं थे, बल्कि रिगिंग होती गयी, हर दफा रिगिंग होती गयी और अपनी मर्जी के लोगों को वहां लाया गया । फिर इसके बाद करोड़ों रुपयों की मिकदार में ग्रांट दी गयी मगर इंतिहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस मकसद के लिए ग्रांट दी गयी उस मकसद की तकमील नहीं हो सकी और वह पैसा अवाम तक नहीं पहुंच सका। इन तमाम बातों से वे बेजार हो गये थे। यह कहा जाय कि सिर्फ 1989 के बाद काश्मीर में बेचैनी हुई तो मैं इसको तसलीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। पिछले कई सालों से काश्मीर में गड़बड़ होती रही है । इसकी वजह यह है कि वहां के मसलों को गलती से निपटाया गया । फिर हमने यह देखा कि इलेक्शंस जो हुए उनमें जो पैसा गया, जो रिगिंग हुई जो गड़बड़ हुई इन तमाम चीजों के कारण काश्मीर के अवाम में एक बेचैनी पैदा हो गयी और फिर वहां पर फारुख अब्दुल्ला को हटाया गया । कहा जाता है कि खास बी.जे.पी. की या किसी और की मर्जी के किसी एक साहब को गवर्नर बनाया गया । मगर मैं समझता हूं कि गवर्नर को भी मुरीदे इल्जाम करार देना उन गवर्नर के साथ नाइन्साफी है । वे बेचारे क्या कर सकते हैं जबकि सारे साल वहां पर बेइंसाफी होती रही है । मैं यह कहूंगा कि इन तमाम नाइंसाफियों के बाद हमको देखना यह है कि इसकी वजह क्या है । एक तो इलेक्शन के ताल्लक से है । वे लोग यह सोचते हैं कि हमारे सही नुमाइंदे नहीं आये, पैसा जो मिला वह उन तक नहीं पहुंचा। फिर दफा 370 की जो बात है वह इंतिहाई अहम है । एक मखसूस मौका 370 की वजह से काश्मीरियों को दिया गया था । वह आर्टिकिल 370 काश्मीरियों के सिर पर तलवार की तरह लटक रही है और काश्मीरी यह समझ रहे हैं कि कभी भी किसी वक्त भी वह आर्टिकल बर्खास्त की जा सकती है और हमारा स्पेशल मौका, खुसूसी मौका जो दिया गया था उसको खत्म किया जा सकता है । जरूरत इस बात की है कि काश्मीरियों में एतमाद पैदा करें और उनको कहा जाए कि आर्टिकल 370 बहरहाल, बाकी और बरकरार रहेगी ताकि उनमें एक इत्मीनान की सांस आये । फिर इससे हटकर पिछले 4–5 सालों से हम वहां क्या देख रहे हैं कि वहां की मइशत बिल्कुल ठप्प होकर रह गयी है । वहां की जो असल मइशत, इन्कम थी वह टूरिज्म से थी । उसका क्या सूरतेहाल है । टूरिज्म इंतिहाई तबाह हो गया है यानी काश्मीर की तीन चौथाई इन्कम इंटरनेशनल टूरिज्म की वजह से थी । आज कोई भी सैयाह कोई भी टूरिस्ट वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, हत्ता कि हिंदुस्तान का भी कोई टूरिस्ट वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से टूरिज्म की वजह से वहां की बरबादी हो गयी है । फिर दूसरी वजह

जो है वह यह है कि फलों की जो काश्त वहां होती थी उसके ताल्लुक से खातिरखाह काश्त नहीं हो रही है और खातिरखाह सबसिडी जो किसानों को मिलनी चाहिए वह भी खत्म हो गयी है। फिर वहां की जो दस्तकारी है उसकी निकासी मुश्किल मसला हो गयी है। किस तरह से वहां हैंडीक्राफ्ट्स की या जो चीजें बनती हैं उनको डिस्पोज आफ किया जाए किस तरह से उनकी निकासी हो सके जब टूरिस्ट ही नहीं आ रहे हैं। ये कई मसले ऐसे हैं जिनकी वजह से आज कश्मीर का मौका इंतिहाई नाजुक हो गया है। फिर एकता यात्रा के ताल्लुक से कई भाइयों ने कहा है। मैं भी यह कहूंगा कि एकता यात्रा जो निकाली गयी है, मैं समझता हूं कि वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए इस एकता यात्रा की कतई जरूरत नहीं थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि एकता यात्रा निकाल करके आपने क्या पाया। एकता यात्रा निकालकर आप कुछ भी नहीं कर सके बल्कि आपने सारी दुनिया को यह बतला दिया कि काश्मीर में अगर आप झंडा लहरा सकते हैं तो सिर्फ फौज की मौजूदगी में लहरा सकते है, अवाम की मौजूदगी में नहीं लहरा सकते हैं। यह इंतिहाई अफसोस की बात है कि इसमें हमारे हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार है। जब जम्मू से वह नहीं जा सकते थे, तो क्या वजह है कि उनको एयरलिफ्ट किया गया और हवाई-जहाज की सहूलियत दी गई है? यह अभी भी क्वश्चन मार्क बना हुआ है और हमारे मोअज्जिज वजीरे दाखला, होम मिनिस्टर साहब से मैं कहना चाहता हूं कि वह अपने जवाब में इसकी सराहत करें कि क्यों उनको हवाई जहाज मुहैया किया गया और क्यों हवाई-जहाज के जरिए उनको श्रीनगर पहुंचाया गया?

मैं तो यह कहूंगा कि एकता यात्रा में हुकूमत भी बराबर बी०जे०पी० के साथ शामिल है और दोनों ने मिल कर वहां पर इस किस्म का तमाशा किया। मुझे इनतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारी दुनिया के अवाम स्टार टी० वी०, सी०एन०एन० और बी०बी०सी० टी० वी० के जरिए यह देखता है कि अब श्रीनगर में कोई भी तिरंगा झंडा अवाम की मौजूदगी में नहीं लहराया जा सकता, सिर्फ फौज की मौजूदगी में ही झंडा लहराया जा सकता है। कितने अफसोस की बात है कि इस किस्म का मोआफिक लाकर खड़ा किया गया। इससे हट कर के क्या हुआ? (समय की घंटी) यह मैं जानना चाहता हूं।

लिहाजा, अभी बातें तो बहुत सी कहने की हैं, पर टाईम की कमी की वजह से मैं इसको मुख्तसर में कहना चाहता हूं। मैं आपके तवस्सुफ से हुकूमत से दर्खास्त करूंगा कि आप कश्मीरियों में ऐतमाद पैदा कीजिए कि आर्टिकल 370 को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, वहां के टूरिज्म और हैंडिक्राफ्टस को तरक्की दी जाएगी, वहां के जरात को तरक्की दी जाएगी और फिर वहां के जो बड़े-बड़े ओहदे हैं, उन पर मुकामी लोगों को लेकर आइये, बजाए इसके कि आप बाहर से, यानी कि हिंदुस्तान के दूसरे सूबों से लाकर आप जो डेप्यूट कर रहे हैं, उसकी बजाय वहां के जो मुकामी बड़े ओहदेदार हैं, अफसर हैं, उनको आप वहां पर मुतैयन कीजिए, ताकि उनमें एक किस्म का ऐतमाद पैदा हो सके और फिर वह यह समझ सकें कि बाकयतन हिंदुस्तान की हुकूमत हमारे साथ मुसलसल इनसाफ कर रही है।

शुक्रिया।

شری محمد خلیل الرحمٰن (آندھرا پردیش): جناب وائس چیئرمین صاحب، کشمیر کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو انتہائی احتیاط کے ساتھ نپٹانے کی ضرورت ہے اور ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ۱۹۴۷ عیسوی میں جب کشمیر کا الحاق ہندوستان سے ہوا تھا، ابھی جیسے کہا گیا مشرا صاحب کی جانب سے کہ ہندوستان سیکولر ملک ہے۔ لہٰذا ہم کو سیکولر ملک کے ساتھ رہنا چاہیئے۔ یہ سمجھ کر کشمیر کے عوام نے شیخ عبداللہ کے قیادت میں کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کیا تھا مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان پچھلے چالیس بیالیس سالوں میں جس طرح سے کشمیر کے مسئلے کو ڈیل کیا گیا، ابتدا سے اور ابتدا ۱۹۵۳ سے شروع ہوتی ہے، جبکہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا جس کی قیادت میں کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہوا تھا، شیخ محمد عبداللہ کو گرفتار کرنے کی کوشش اس بات کی کی گئی کہ بخشی غلام محمد جیسے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ کو وہاں کا چیف منسٹر بنایا جاتے۔ کئی سال تک بخشی غلام محمد کی حکومت چلتی رہی، مگر پھر یہ محسوس کیا گیا کہ اقتدار دوبارہ شیخ محمد عبداللہ کے حوالے کیا جائے۔ اس وجہ سے کہ شیخ عبداللہ ہی ایک واحد لیڈر تھے تمام جموں کشمیر کے عوام کے جو کہ ان کے آئینہ دار تھے اور وہاں کے مظہر تھے۔ چنانچہ یہ سمجھ کر شیخ محمد عبداللہ کو دوبارہ چیف منسٹر مقرر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد شیخ محمد عبداللہ کے انتقال کے بعد فاروق عبداللہ کو وہاں چیف منسٹر بنایا گیا۔ فاروق عبداللہ کے تعلق سے بھی دیکھا گیا کہ فاروق عبداللہ کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی اور جی ایم شاہ کو کچھ دنوں کے لئے چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ لہٰذا واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جس طرح سے کشمیر کے مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیئے تھا۔ اس طریقے اور احتیاط کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو ڈیل نہیں کیا گیا۔ پھر اس دوران میں کئی الیکشن وہاں کرائے گئے۔ جیسے کہ کل ہی میرے محترم بزرگ جناب سکندر بخت صاحب نے کہا تھا۔ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس حد تک کہ جتنے بھی الیکشن وہاں پر کرائے گئے۔ صحیح معنوں میں وہ الیکشن نہیں تھے بلکہ رگنگ ہوتی گئی۔ ہر دفعہ رگنگ ہوتی گئی اور اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں لایا گیا۔ پھر اس کے بعد کروڑوں روپیوں کی مقدار میں گرانٹ دی گئی مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

پڑتا ہے کہ جس مقصد کے لئے گرانٹ دی گئی اس مقصد کی تکمیل نہیں ہوسکی اور وہ پیسہ عوام تک نہیں پہنچ سکا۔ ان تمام باتوں سے وہ بیزار ہو گئے تھے۔ یہ کہا جائے کہ صرف ۱۹۸۹ کے بعد کشمیر میں بیچینی ہوئی تو میں اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ پچھلے کئی سالوں سے کشمیر میں گڑبڑ ہوتی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے مسئلوں کو غلطی سے نبٹایا گیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن ہوتے ان میں جو پیسہ گیا۔ جو رگنگ ہوئی جو گڑبڑ ہوئی ان تمام چیزوں کے کارن کشمیر کے عوام میں ایک بیچینی پیدا ہوگئی اور پھر وہاں پر فاروق عبداللہ کو ہٹایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خاص بی۔ جے پی۔ کی یا کسی اور کی مرضی سے کسی ایک صاحب کو گورنر بنایا گیا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کو بھی مورد الزام قرار دینا ان گورنر صاحب کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں جبکہ سارے سال وہاں پر ناانصافی ہوتی رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان تمام ناانصافیوں کے بعد ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو الیکشن کے تعلق سے ہے۔ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے صحیح نمائندے نہیں آتے۔ پیسہ جو ملا وہ ان تک نہیں پہنچا۔ پھر دفعہ ۳۷۰ کی جو بات ہے وہ انتہائی اہم ہے ایک مخصوص موقع ۳۷۰ کی وجہ کشمیریوں کو دیا گیا تھا وہ آرٹیکل ۳۷۰ کشمیریوں کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے اور کشمیری یہ سمجھ رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی وقت بھی وہ آرٹیکل ۳۷۰ برخاست کی جاسکتی ہے اور ہمارا اسپیشل موقع خصوصی موقع جو دیا گیا تھا اس کو ختم کیا جاسکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیریوں میں اعتماد پیدا کریں اور ان کو کہا جائے کہ آرٹیکل ۳۷۰ بہرحال باقی اور برقرار رہے گی تاکہ ان میں اطمینان کی سانس آئے۔ پھر اس سے ہٹ کر پچھلے چار پانچ سالوں سے ہم وہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی معیشت بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے وہاں کی جو اصل معیشت، انکم تھی وہ ٹورزم تھی۔ اس کی کیا صورت حال ہے۔ ٹورزم انتہائی تباہ ہو گیا ہے یعنی کشمیر کی تین چوتھائی انکم انٹرنیشنل ٹورزم کی وجہ سے تھی۔ آج کوئی بھی سیاح وہاں کوئی بھی ٹورسٹ وہاں جانے کے لئے تیار نہیں ہے۔ اس طرح سے ٹورزم کی وجہ سے وہاں کی بربادی ہو گئی ہے۔ پھر دوسری

وہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز کی جو
کمپنی وہاں ہوتی تھی اس کے تعلق
سے خاطر خواہ کاشش نہیں ہو رہی
ہے اور خاطر خواہ سبسڈی جو کمپنیوں
کو ملنی چاہیئے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔
پھر وہاں کی جو دستکاری ہے اس کی
نکاسی کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کس طرح
سے ان کی نکاسی ہو سکے جب ٹورسٹ
ہی نہیں آ رہے ہیں۔ یہ کتنے مسئلے ایسے
ہیں جن کی وجہ سے آج کشمیر کا موقع
انتہائی نازک ہو گیا ہے۔ پھر ایکتا یاترا
کے تعلق سے کسی بھائیوں نے کہا ہے
میں بھی یہ کہوں گا کہ ایکتا یاترا جو نکالی
گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی
نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایکتا
یاترا کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ میں یہ
پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایکتا یاترا نکال
کر کے آپ نے کیا پایا۔ ایکتا یاترا نکال کر
آپ کچھ نہیں کر سکے۔ بلکہ آپ نے
ساری دنیا کو یہ بتلا دیا کہ کشمیر
میں اگر آپ جھنڈا لہرا سکتے ہیں
تو صرف فوج کی موجودگی میں لہرا
سکتے ہیں۔ عوام کی موجودگی میں
نہیں لہرا سکتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس
کی بات ہے کہ اس میں ہماری حکومت
بھی برابر کی ذمہ دار ہے جب جموں
سے وہ نہیں جا سکتے تھے تو کیا وجہ
ہے کہ ان کو ایئر لفٹ کیا گیا اور ہوائی
جہاز کی سہولیت دی گئی ہے۔ یہ ابھی
بھی کنفیوژن ہے کہ بنا ہوا ہے اور
ہمارے معزز وزیر داخلہ۔ ہوم منسٹر
صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ
اپنے جواب میں اس کی صراحت کریں۔
کہ کیوں ان کو ہوائی جہاز مہیا کیا گیا
اور کیوں ہوائی جہاز کے ذریعے ان کو
سری نگر پہنچایا گیا۔

میں تو یہ کہوں گا کہ ایکتا یاترا
میں حکومت بھی برابر بی۔ جے۔ پی۔ کے
ساتھ شامل ہے اور دونوں نے مل کر
وہاں پر اس کا تماشہ کیا۔ مجھے انتہائی
افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ساری
دنیا کے عوام نے اسٹار ٹی۔ وی۔ سی۔ این۔
این اور بی۔ بی۔ سی۔ ٹی۔ وی کے ذریعہ
یہ دیکھا ہے کہ اب سری نگر میں کوئی
ترنگا جھنڈا عوام کی موجودگی میں نہیں
لہرایا جا سکتا۔ صرف فوج کی موجودگی
میں ہی جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے کتنے
افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کا موقف
لا کر کھڑا کیا گیا۔ اس سے ہٹ کر کے گیا
ہوا۔ "وقت کی گھنٹی" میں یہ جاننا چاہتا

ہوں۔ لہٰذا ابھی باتیں تو بہت کہنے کی ہیں پر ٹائم کی وجہ سے میں اس کو مختصر میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے توسط سے حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ کشمیریوں میں اعتماد پیدا کیجئے کہ آرٹیکل ۳۷۰ کو برخاست نہیں کیا جائے گا وہاں کے ٹورزم اور ہینڈی کرافٹس کو ترقی دی جائے گی۔ وہاں کی زراعت کو ترقی دی جائے گی اور پھر جو وہاں بڑے بڑے عہدے ہیں۔ اُن پر مقامی لوگوں

کو لے کر آئیے۔ بجائے اس کے کہ آپ باہر سے یعنی ہندوستان کے دوسرے صوبوں سے لاکر آپ جو ڈپوٹیشن کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے وہاں کے جو مقامی بڑے عہدیدار ہیں۔ افسر ہیں ان کو آپ وہاں پر متعین کیجئے تاکہ ان میں ایک قسم کا اعتماد پیدا ہو سکے اور پھر وہ یہ سمجھ سکیں کہ واقعی ہندوستان کی حکومت ہمارے ساتھ انصاف کر رہی ہے۔ (مداخلت)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Shri Shabbir Ahmad Salaria.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir) : Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Now, our understanding—let's be clear about it.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : The understanding is there, there is no doubt about it, but...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Not "but".

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : ...the matter is so important. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Please cooperate.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : I will do the best possible.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : He is from Kashmir but doesn't live in Kashmir !

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA :

आज वह कश्मीर है महकूम व
मजबूर व फ़क़ीर,
कल जिस कहते थे अहले नज़र
ईरान-ए-सग़ीर,
आह वह क़ौम नजीब व चरब
दस्त व तर दिमाग़,
है कहां रोज़-ए-मकाफ़ात
ए ख़ुदा दारो गीर।

آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر
کل جسے کہتے تھے اہل نظر ایران صغیر
آہ! وہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ
ہے کہاں روز مکافات اے خدائے دیر گیر

These are the verses sung by Allama Iqbal on the deplorable conditions prevalent in Jammu and Kashmir prior to the Independence of India Act. But there has been no change for the better since then in Jammu and Kashmir.

[ ] Transliteration in Arabic Script.

[Shri Shabbir Ahmad Salaria]

The Home Minister has asked for extension of President's Rule in Jammu and Kashmir for another six months because, according to him, democracy cannot be restored in Jammu and Kashmir, and I can foretell that with the policies of repression that are being pursued in Jammu and Kashmir, he will be obliged to come to this House to ask for more extensions.

Today Jammu and Kashmir is separated into two parts by a bloody and artificial ceasefire line which passes through the heart of Kashmir, dividing its villages, mountains and meadows, nay, even the houses, shrines and families of Kashmir. An area of about 27,000 square miles and over 29 lakh people of Jammu and Kashmir are on that side and an area of 57,000 square miles and about 71 lakh people are on this side. Kashmiris can never be at peace unless the ceasefire line, now called the line of actual control, is removed and the territory and the people of Jammu and Kashmir are reunited.

It has been argued by the BJP—which poses the greatest possible threat to the unity of India—that article 370 should be annulled as it was a temporary provision in the Constitution of India as, according to it, this article is the sole root cause of the trouble in Jammu and Kashmir. This betrays efforts deliberately to ignore history. The Maharaja of Jammu and Kashmir who wanted to make it an independent state, was obliged by the revolution in Jammu and Kashmir in the wake of the partition of India and by the defeat of his forces, to enter into a limited accession on foreign affairs, defence, communication and currency with the Government of India in 1947 and to seek military intervention and help. This was accepted by the Government of India subject to approval of the people of Jammu and Kashmir. The case was taken by no one else than the Government of India to the United Nations where at the behest of both India and Pakistan, a resolution was adopted that the future of Jammu and Kashmir would be decided by a plebiscite to be held under the auspices of the United Nations. Pakistan was called upon to withdraw its forces from the occupied part of Jammu and Kashmir, and India was asked to reduce its forces. At that time the Constitution of India was in the making, and in this context Article 370 which envisages the constitutional relationship between Jammu and Kashmir and the Union of India in the interrugnum, had to be styled as a temporary provision. But all know that that agreed Resolution has not been implemented so far. As such, Article 370 has continued on the statute book as a temporary measure.

Again, it does not make sense to contend that Article 370is the cause of the turmoil in Jammu and Kashmir because there is no such article in the case of Punjab, there is no such article in the case of Assam, there is no such article in the case of Mizoram or in the case of Nagaland, where also there have been movements for freedom and for greater autonomy. In fact, the Sarkaria Commission has already held that if India has to survive as a unit, the division of powers between the Centre and the States shall have to be recast.

It is heartening to note that all the Members cutting across party lines, except for the BJP, have emphasised that series of blunders after blunders have been committed in dealing with Jammu and Kashmir, which have brought into being the present turmoil—the dismissal of Sheikh Mohammed Abdullah in 1953 in an operation coup d'etat, the foisting thereafter of hand picked puppet governments of Bakhshi Gulam Mohammed, Mohammed Sadiq and Mir Qasim from 1953 to 1975, the rigging of elections during the interrugnum to rule Kashmir, the re-toppling of Sheikh Mohammed Abdullah in 1976, the topping of the National Conference Government in

1984, engineered through defections by Shri Jagmohan, the then Governor, sent to Jammu and Kashmir for this specific purpose and ultimately Shri Rajiv Gandhi compelling the National Conference to become a mere appendage of the Congress. This led the people to believe that the National Conference had merged in the Congress, and when they were in search for a party which could safeguard their regional aspirations and cultural interests and in short "Kashmiriat", they were hijacked by communal organisations. The National Front added...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF CHANDRESH P. THAKUR) : Mr. Salaria, you are reading something in detail. Are you consulting a document?

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : No document. These are notes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : They seem to be long notes.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : It is finished now.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal) : It is a finished product.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : The National Front added fuel to the fire when in the face of an ultimatum by the combined Government of the National Conference and the Congress that they would not remain in Government in case he was sent as the Governor of Jammu and Kashmir, he was sent, with the result that the Government of Jammu and Kashmir resigned. Mr. Jagmohan promptly dismissed the Assembly of Jammu and Kashmir, with the result that the only...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : You should avoid personal reference.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : But he is sitting here.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : It is not the person, but it is the institution you are talking about.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : The popular Government resigned. At that time there were only 300 angry boys, armed boys in Kashmir, but a reign of atrocities and excesses was unleashed by the said Governor, which alienated large sections of people who, for this reason, lost all faith with the result that we are now in the quagmire.

It was the result of that that thereafter thousands of Kashmiri *pandits* migrated. It was thereafter that lots of Kashmiris marched to the United Nations offices. It was thereafter that you find that the conditions deteriorated. So, in the circumstances, they have been joined by lots of other Kashmiri Muslims who have also migrated from Kashmir on account of disturbed conditions.

The march of Amanullah Khan, to hich a reference has been made, is not the first march to take place in Jammu and Kashmir. There was a march in 1957, headed by Choudhry Ghulam Abbas also. At that time also a number of persons got killed, many were arrested and many were injured.

If there is a sincere desire to improve the situation in Jammu and Kashmir, then, the Government of India should abjure the policy of suppression and atrocities in Jammu and Kashmir. Otherwise, such actions will further alienate the people of Jammu and Kashmir, and there would be further violations of human rights. What if by suppression a symbolic peace is brought about in Kashmir, which afters ome time is again breached and the posterity

[Shri Shabbir Ahmad Salaria]

has to face the music once again? The Disturbed Areas Act should be immediately withdrawn from Jammu and Kashmir as these have been thoroughly misused and have resulted in corruption.

Secondly the occurrence of excesses such as rapes at Badsgam, Hunnan, Poshpora, Hillar etc. and the killings of innocents in firing and in torture cells in police custody should be avoided. Many such incidents have taken place. They have not advanced our case and have not brought the people nearer to us.

Thirdly, the Government should proclaim a general amnesty for all such people or all such angry boys who are now ready to give up guns so that they can return to normal life.

Fourthly, political leaders and workers now in jails should be released and a political dialogue should be started with them.

Fifthly, the entire administration in Jammu and Kashmir, right from the Chief Secretary, SP, Deputy Commissioner, Commissioner are non-local and non-Kashmiri. In order to inspire confidence among the local masses the local people should be taken in for the purpose.

Sixthly, the Legislative Assembly in Jammu and Kashmir, which was wrongly dissolved by the then Governor, should be revived to start a political process. The Governor's Advisory Council, which has been constituted, cannot achieve that end.

Seventhly, the relationship of the State of Jammu and Kashmir with that of the country should be based on the relationship which was in existence in 1952. It has been contended by Mr. Bakht of the BJP that the per capita fund for the State of Jammu and Kashmir has been the highest as compared to other States of India. He forgets that no other State has been torn and bifurcated in the manner in which the State of Jammu and Kashmir has been. No other State has lost its historical roots and communication and trade routes as the State of Jammu and Kashmir has done. In no other State there is a cease-fire line cutting through the State and dividing the country and snapping its means of livelihood.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : You have far exceeded your time. You have made your point. Now, Prof. Bhattacharjee.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Only one sentence and I will finish.

The 90 per cent grant to which a special category State, the Jammu and Kashmir State, is entitled to, was withheld up to 1991. The arrears on that account should be immediately paid to the State of Jammu and Kashmir so that the financial difficulties which the State is faced with are overcome and the State can progress further.

Last but not least, the political leaders and political workers of all hues, who are in prison and are prisoners of conscience should be released forthwith. With them a dialogue should be conducted so that ways and means can be found to resolve the Kashmir dispute.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : May I speak from here ?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : All right. But take three minutes in the bargain.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : I will try.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the issue has been examined from different angles. A statement is being made by the Government, from time time perhaps somewhat dissimila

other parts of the country that they are interested in opening the dialogue. Even in the speech the question of "within the framework of the Constitution and abjuring of violence" is not being raised so much. This dialogue is essential. But the other refrain is, if elections can be there in Punjab, can it be far behind in Kashmir ? If the elections of the type of Punjab are enacted in Kashmir let me humbly submit, that will lead to further alienation of the people of Kashmir Valley and Kargil, if not Jammu and Ladakh. We should not treat them as separate units. They are really part of one entity. We should look at them as such but not otherwise. Therefore, elections by trick will not serve any purpose. If elections are held properly only then it will serve some purpose. Let that lesson be taken by the Government. Let not the Government repeat the mistake of what was done on the 25th and 26th January when the BJP President was catapulted to Sirnagar and was made to unfurl the national flag at Lal Chowk by forcible cooperation of all the people there, even before the State function. The State function was held later. This alienated not only the people of Kashmir but others also elsewhere. Some temporary advantage may be derived out of it. I do not know. But it will do incalculable harm to our cause in Kashmir in the long run. We should be very much aware of that.

I may not subscribe to all that has been suggested by my friend, Mr. Salaria. But on certain specific points like releasing the young men, releasing the political leaders and opening of the dialogue there. I wholeheartedly support him. I think the Government should seriously undertake this task during this period of extension of President's rule. So far as extension of President's rule is concerned, we are opposed to it. But in the case of Kashmir, there is no alternative and it is a mere formality. Let it be the last extension of President's rule in Kashmir and let a popular rule be restored, whatever be the verdict of the people of Kashmir. If they are allowed to exercise their franchise and if they give their verdict, really the political climate there would change.

So far as I know, the main grievance of the young men of Kashmir people is against the previous elections that were totally rigged. It was not their verdict. Let a repetition of the same thing or a repetition of the Punjab experiment be not repeated. Ten per cent of the votes really do not determine the power. Let that situation be not repeated. Thank you. (Ends).

SHRI JAGMOHAN (Nominated) : Thank you very much, Sir.

I think the problem of Kashmir has not been solved for the last so many years primarily because... (*Interruptions*).. we are not recognising the facts and I personally feel that the nation is paying a very heavy price for falsification of facts. What I hear here is really vey strange. It is all against the documents, all against the written records. I do not know what the future generations will think of us. Was this the nation which produced Mahatma Gandhi ? Here, It was said that Sheikh Abdullah was wrongly imprisoned and dismissed. But the root cause of the Kashmir problem is the politics of deception. Because of paucity of time, I will not go into the detail. But let me tell you this. From the day one, when Kashmir acceded to India, when Sheikh Abdullah was saying, "We have given our hands to India and we have finally decided to be with India", he was hobnobbing with the Americans. There is a note recorded on January, 1948 by Austin of the State Department in which he says, "Sheikh Abdullah wants to have an Independent Kashmir". What about this written record ? He gave an interview to Michael Davidson in April, 1948. Whereas he was talking to India on different terms, he was hobnobbing with other powers. He met the American Ambassador Adlai Stevenson in 1953 and made arrangement for the working for the

[Shri Jagmohan]

independence of Kashmir. And after few days, "The New York Times" produced a map in which they showed the map of Independent Kashmir. There are many documents like that. When you see the Henderson Paper then they come out, you will know to what extent the nation has been deceived. There are many other documents. All I would like to say is, because of this gentleman about whom so much has been said, Panditji got a very bad name at the international level, because of what he was saying about Kashmir. What does Sheikh Abdullah write in Atish-e-Chinar ? How he repays Panditji ? It is a written document. He writes,

> "....he (Panditji) was a great admirer of the past heritage and the Hindu spirit of India. His interpretation of the Indian history, though not always based upon accurate knowledge, approximates to the interpretation of revivalists like K. M. Munshi and Dayanand Saraswati."

This is the language of a secularist !

> "In Nehru's outlook, therefore, imprints of Machiavelli's political philosophy and jugglery are found."

I do not want to quote the whole thing which takes time.

> "That is why the disciple of the principled philosopher and saint, Mahatma Ghandhi, was at the same time very much fond of Chanakya. Jawaharlal Nehru employed Machiavellian approach towards us in Kashmir. He dealt with Pakistan in the same fashion. At international level also he exhibited the same Machiavellian outlook... "

It is all in Atish-e-Chinar, his own biography. You read my book. It is all documented. It is written there.

श्री राम नरेश यादव (उत्तरप्रदेश) : एक बात ये बता दें इतना कहने के बाद कि डा. अब्दुल्ला जी ने और कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ एक्शन किया के नहीं किया, भारत के साथ अपना विलय किया के नहीं किया? अपना सारा विकास भारत के साथ दिया के नहीं दिया ? इसका क्या जवाब है ?..(व्यवधान)...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Mr. Vice-Chairman, we want to listen to Mr. Jagmohan. Kindly allow him to speak because he has always been attacked in this House. Let him say what he wants to. (*Interruptions*) say. He had been in Kashmir as Governor and knows things better.

श्री राम नरेश यादव : यह एक तथ्य को जिस तरह से झुठलाने की कोशिश की जा रही है...(व्यवधान)

श्री अवन्तराय देवशंकर ध्रुवे : सत्य नहीं झुठलाया जा सकता । वह सत्य बात कह रहे हैं, लैटर की बात कह रहे हैं। ..(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRGESH P. THAKUR) : Please continue.

SHRI JAGMOHAN : This is only proving my point that this nation is not willing to listen to the truth and we--all of us, whether in Kashmir or in India as a whole—are suffering for that. If the question has 4.00 P.M. been asked, you give me time, I will give you the page number. This is the page number of "Urshe-Chinar"—351,355. It is written in Urdu and it is translated in the book by me and I have quoted it at page 131 and it is all written there. It is a big thing. (*Interruptions*). All documentation is there.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : I think, you continue

with your statement. Forget about this. (*Interruptions*).

SHRI JAGMOHAN : It is not my publication. It is "Urshe-Chinar"—Sheikh Abdullah's biography.

शेख अब्दुल्ला साहब का जो लैंग्युएज है वही मैं पढ़ रहा हूं । लेकिन आप सुनने को तैयार हों तो मैं बताऊं । मैं जब भी बोलता हूं आप सुनने को तैयार नहीं.... (व्यवधान)

उपसभापतिपद (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : जगमोहन जी, ज्यादा अच्छा होता कि यह बताइये कि अब क्या हो ?

श्री संघ प्रिय गौतम : और वह जो किसी ने बताया नहीं है, वह बताइये आप.... (व्यवधान) और तथ्यों की जानकारी दीजिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Mr. Gautam don't interrupt.

(*Interruptions*)

SHRI JAGMOHAN : If you want to hear me. I will speak. Otherwise, I will sit down.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Please continue.

SHRI JAGMOHAN : My point is, I will come to the solution also. But you must understand if you want to have a solution, the disease should be diagnosed correctly. If the disease is something else and you are treating for something else, you will come to the same situation as you found yourself in. This is what I was saying. Who has played the politics of deception ? That should be clearly understood. There are many other details which are mentioned there which if you want to read, you can read.

Second point I want to mention is, it was stated here that Gandhiji in 1947 saw a ray of hope in Kashmir. I have quoted extensively from the nature of Kashmiri Islam which was very catholic, which was very tolerant, which was traditional to Kashmir and had a very great quality of catholicity and compassion. Who fundamentalised this Islam ? This is what we should understand. Who brought this in ? Who issued the Fatwas ? I will just quote one thing. The National Conference workers in 1983 elections and later in 1987 elections, found fault with the Chief of Umday Islam, Qazi Nissar, and it is Qazi Nissar, who gave a speech which I have quoted, in which he says :

"Who sold us to misuse religion; who spoke from Hazrat Bal, who gave Fatwas that you should not give even a graveyard of land for the Congressmen, who showed us the green handkerchief ; who said that all rivers go to Pakistan, who taught us all this, who taught us to misuse religion ? When elections took place in Kashmir in 1977, whose party workers took Quran in one hand and the voters appeal in the other hand ?" It is not my thing. It is Qazi's Nissar thing. He said, "who did this ?"

I have many other things to show but I won't I would just show this poster of the National Conference of 1983 elections. They show Kashmir and they show the hand killing a small child in Kashmir. It is the National Conference and the significance of hand you know. They show—this is the Indian Army having all these bayonets on Kashmir. (*Interruptions*)

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : This was after defection. (*Interruptions*)

SHRI JAGMOHAN : So many facts have been falsified. Let me show this. What does it say ? I will read in Urdu after showing this child chained, and everything :

[Shri Jagmohan]

तोड़ इस दस्त शिकन को यारब
जिसने रूहे-आज़ादी-ए-कश्मीर को पामाल किया ।

इस जफ़ा कश हाथ को काट डालिए ।

किसका हाथ है ये ? क्या कह रहे हैं आप ?

Why do you want to falsify the facts ? These are the facts. The entire Kashmir policy...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Let him complete. Every Member has a right to speak.

(*Interruptions*)

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : £

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : That is not going on record... (*Interruptions*)... Everybody has a right to speak. You must cooperate with them just as others cooperate with you.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : If such details are to be given, then give us time and we will also give...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : You had your time.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : No, I didn't have so much time. I didn't have that much of indulgence.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : You have attacked him personally. Don't interrupt him. Let him speak what he wants to say. He is revealing very important facts. (*Interruptions*)

£Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : No, no ; it is a different Jagmohan. He is not the Governor any more.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : At that time whatever he did,...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Please sit down. It doesn't help...(*Interruptions*)...

SHRI JAGMOHAN : If you want to listen, I will speak ; otherwise, I don't want to speak... (*Interruptions*)...I have always been interrupted. I am always interrupted because truth is bitter. Nobody wants to listen the truth in this respect.

मौलाना अबदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश) : मैं गुज़ारिश करूंगा कि आप बोलें । हम लोग बहुत शौक से सुनेंगे .... (**व्यवधान**) आप लोग बीच में मत बोलें । और भी बहुत बोलने वाले लोग हैं ।

†[مولانا عبید اللہ خاں اعظمی

(اتر پردیش) : میں گزارش کروں گا کہ آپ بولیں - ہم لوگ بہت شوق سے سنیں گے: — (مداخلت)... آپ لوگ بیچ میں مت بولیں - اور بہت بولنے والے لوگ ہیں -

SHRI JAGMOHAN : My point is...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Make quickly summary points.

SHRI JAGMOHAN : Sir, if you think I am not speaking pointedly...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Please go ahead. Permission is my privilege. That is no problem.

‡[Transliteration in Arabic Script]

SHRI JAGMOHAN : The basic point which I am making is, since 1947 onwards the entire politics of Kashmir has been run on creating anti-India sentiments. The National Conference leadership has tried to build itself on such sentiments. We must understand that it is this disease which exists. And who has told the youth to do what they are doing today. What happened during the Resettlement Act ? What happened during the Plebiscite Front ? What happened during the Al Fatah agitation ? These are all facts recorded in history and I would request the Central Government to go through all these records and base its conclusions on documents and not on what is said loosely without any verification.

One of my friends here said that I was instrumental in engineering defections. What a charge it is ! I was the person who had recommended even on July 2, 1984 imposition of the Governor's rule. I had not recommended installation of G.M. Shah. It is all recorded on your records. It is in my telegrams to the President which exist and I have resisted saying all this and I have suffered in silence all the disinformation. But you go on saying it. All I have to say is, you see the documents as to what I had recommended...*(Interruptions)*...

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : What is the relevance ? ...*(Interruptions)*...

SHRI JAGMOHAN : Please listen to me. Is it sensible to believe that I will engineer a defection and then ask the Government and then the Government will turn down my recommendation ? Any how, forget about it. I am appealing to the sense of the House to draw its own conclusion. You may think that I am not right, I am wrong. What I am trying to say is, please base your conclusions on documents and not on hearsay or falsehood. Then comes 1990 when Mr. Jagmohan was sent there at the behest of somebody. Now I have documented all that which was said in 1986 when the Governor's rule was there. I went there for the first time in April, 1984. What were the conditions at that time ? They were all documented. How many bomb explosions were there ? They were all written by Mr. P.C. Sethi in his documents and you kindly go through them, what was going on in that part of the country. And if you want to see the documents of this very House, of the Lok Sabha debate of 30th July, 1984, You see what Mrs. Bajpai had said about what Shri Farooq Abdullah was doing at that time ; what Mr. Kamaluddin had said. It is all documented. If you want to hear I can read it out to you. If you like I will only read one of Shri Baliram Bhagat. You will see what he was saying at that time and what the activity was at that time. I tried my best to control the situation and the situation was controlled. When I came in 1989 I had been warning that things were going from bad to worse and the basic reasons for that were not what they had said. It was said that when I went there the situation became bad. It was said that when I went there for the second time the situation had deteriorated. But what do the facts say ? The facts say that during 1989 there were 1600 cases of violent incidents. The facts say that 315 bomb explosions were there before I went there. The facts say that the District Magistrates were not signing the warrants of detention. The facts say that the Advocate General did not appear in those cases. It is not that I am saying it. It was there in all national dailies. You see the records which I had documented. They say that there was no Government in Kashmir. There was nothing of the sort. When Rubiya Sayeed was kidnapped, neither the Central Government nor the State Government knew what had happened. Absolutely the State had been taken over. The internal subversion has been completed. The IB officials had been killed. The

[Shri Jagmohan]

District Magistrate who had tried Maqbool Bhatt had been killed. Sithalal Sapru had been killed. P.N. Bhatia had been killed. All records are there. Still they blame me for the 1600 cases of violent incidents. Your own Parliament had made the statement. I was asked to go there. I was reluctant to go there. I said, "I had a very good innings. I don't want to go." Because everyone was telling that the situation was so tense and Kashmir had been lost. I said, "All right, if you want me to go, I will go. I will not charge any salary because people may say that Jagmohan is asking for a second term." This is what I am getting now in return. This is what I am getting in return when I tried my best to get it back for India. This is what was being said. I am not for 'A' or 'B' or any political party. I went only for the country. This is what you have done to me, blaming against all facts. What are you doing now ? "Mr. Jagmohan has brought the Kashmiri Pandits." You see the press note of 7th March, 1991, which says about my appeal and I want to read it out to you. I would like to put it on the record of the House. What did Jagmohan do ? He sent an appeal to the Kashmiri Pandits to return to stay there. I would make camps for them in Srinagar if they were feeling threatened. They got threatened because so many of them were killed. There is written document even to General Rao. It was said that 25,000 Kashmiri migrants had moved. So many Kashmiris had been killed. This is all in writing. No action has been taken by the State Government and, therefore, they were migrating. It was all done before I went there. On 13th January, 31 people were injured and 19 people were killed in Kashmir. I went on 19th January to assert the authority of the State to bring back the levers of power. What was the casualty ? Twenty-seven. When they want to have a complete show of independence they bring 10,000 or 1,00,000 people to the Idgah. I did not allow this to happen. No Bluestar. Nothing of the sort. With the minimum of casualties I was able to re-settle the whole machinery back into path. What happened in May ? Killings are now three times more. Kidnappings are now three times more. So many things are more than this. I don't want to blame anyone for that. But I want to say one thing only.

I was able to shift the capital in May by the same road by which you have not been able to take even 50 trucks. I brought all the employees from Jammu to Srinagar. I brought the capital there. I do not say that I did it for 'A' or 'B'. I did it only for the country. The authority should be asserted. We are all for justice, for truth, for fairness and for fearlessness. That was my policy. He says, in 1958-59 I went there. All records say what the Kashmiri Muslims think of me. It is there in the newspapers. It is there in the vernacular press. I have documented it. Yet they go on saying the opposite. The country is being punished for living with lies. I am sure the suffering of ours is because of this culture of superficiality, culture of shallowness. I am not blaming anyone. Please forget about it. I am only saying that our country is passing through a very critical phase, where we are living in a superficial...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : You can speak more when the Kashmir budget will be discussed.

SHRI JAGMOHAN : I don't want to take a minute more than the allotted time. I know that very few people want to hear the truth. If they want, I can...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : You can make your concluding observation if you like

SHRI JAGMOHAN : I would like to adopt a constructive approach. The constructive approach is, I had gone there, assessed the situation very clearly. I was very clear in my mind. There are four aspects of the situation which need to be gone into. The first important thing is, assert the authority of the State in a sustained way, not doing something today and something else tomorrow. Just have a sustained policy till the sway of kalashnikov is either eliminated or reduced to a very insignificant level. If it is done, only then you would be able to get, out of the militants moderate elements who will be willing to talk to you and settle with you. We must be very clear. We should make it very clear As I have said, we are not interested in X, Y or Z or in any individual or party. We are interested in being fair and just. We will hold fair and free elections, but not under the threat of violence. That is why I dissolved the Assembly. I wanted to give a line of retreat to the youngsters, the moderate out of this who would come to us. They were coming and I am quite confident that they would have responded to my gesture. By this time, by having free and fair elections out of these people who had gone astray, we could have had a new youthful leadership. Why has it happened ? People don't understand because we blocked the aspirations of the people. We blocked even the honest and meaningful people. We set up a corrupt and callous oligarchy whose interest was to mislead people, whose interest was to go on speaking about Article 370 irrespective of the fact that Article 370 was keeping Kashmir impoverished. It is a different matter. So, the first thing is, keep a sustained pressure. Secondly, under that pressure militants or moderate elments out of this will come to you and discuss with you. You just assure that you will hold fair and free elections. Then to deal with the Pakistan agency, you must set up an equally guerrilla tactics war which would work within the organisation of those very parties. Then we will be able to settle with them.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Sir, I have a small question to ask.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Let him complete.

SHRI V. NARAYANASAMY : When he was the Governor of Jammu and Kashmir, the leaders of political parties and Members of Parliament went there. There in the meeting he said that his first duty is to eliminate Muslims from Jammu and Kashmir. Did he say that or not ? In the presence of all the political leaders, did he say that or not ?

SHRI JAGMOHAN : Sir, I have never said that. I repeat, I have never said that. I have written documents and I am...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : You come back to the point.

डा० एत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, इन दोनों में सत्य कौन बोल रहा है .... (व्यवधान) ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : आप तब तक बैठ जाइये और कार्यवाही में सहयोग दीजिए ।

SHRI JAGMOHAN : I would make my submission about article 370 also because I feel there is a lot of wrong notion about this article. I will not go into the historical background ; that would require a lot of time. The point is, there are two serious drawbacks of article 370 which we must recognise. It is keeping three regions of the State under perpetual tension ; Ladakh vs. Valley ; Jammu vs. Valley. The people of Ladakh as far back as 1948 had made a representation to Panditji saying that if he wanted to keep them as perpetual slaves of the valley, then it was

[Shri Jagmohan]

as good as living under the Chinese. Similarly, with Jammu, you know what the position is like. Another thing is that article 370 is being misused. I have my grave objection against the misuse of article 370. I can give you one example. I would appeal to the Home Minister to set it right while we have President's rule in the State. It is about the displaced persons who had come from Pakistan in 1947. They came here due to compulsion of circumstances. It is very unfortunate that these people have no citizenship rights in spite of having lived there for 45 years. Their children cannot get admission in any professional college. They cannot vote and neither can they become members of cooperative societies. They cannot get loans. They don't get Government jobs. These are people who had come here not for a holiday, but due to compulsions. The matter went to the Supreme Court. The Supreme Court said that it was sorry to note these conditions but because of article 370, because of the separate Constitution and because of separate citizenship rights, it could not give any relief to these people. But at the same time it said that the State Government could easily modify the local laws and can give these people rights. Now, we have been fighting for human rights in South Africa. We have been fighting for human rights in Palestine. But in our own country for the last 45 years. If the Commitment of this country to the principle of justice is this, then—God save it——
...(*Interruptions*)...

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Article 370 does not stand in the way of the State Government...(*Interruptions*)...

SHRI JAGMOHAN : All right, All right. (*Interruptions*)...

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : You, yourself said that..(*Interruptions*)...

SHRI JAGMOHAN : You can see the judgement of the Supreme Court and Jam only requesting the Government...(*Interruptions*)...

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : There has been no misuse...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : आप एंथ्यूसिएज्म में बहस को लम्बा कर रहे हैं । अब आप बैठ जाइये।

श्री शब्बीर अहमद सलारिया : जनाब हमको तो दो मिनट मिलते हैं और यहां बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं । हमको ऐसा मौका मिले तो हम तो जन्नत में पहुंच जाएंगे ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) पहुंचाएंगे आपको भी ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : मैं यह कहना चाहता हूं कि..... (**व्यवधान**) ।

SHRI JAGMOHAN : I will explain...(*Interruptions*)...

SHRI ASHIS SEN (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, may I know whether there is any time allocation for the discussion... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : That does not help ...(*Interruptions*)...

SHRI ASHIS SEN : There must be some time allocated. He is consuming the time of all the other Members...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY : Do you want us to believe what he says now ?...(*Interruptions*)

श्री संघ प्रिय गौतम : हमारी पार्टी का समय भी इनको दे दिया जाय।.... (**व्यवधान**)

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : 45 मिनट हो गये हैं, 45 मिनट.... **(व्यवधान)**...एक्स्ट्रा टाइम 45 मिनट दिया गया है, पार्टियों का समय बढ़ाने के बाद भी 45 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। **(व्यवधान)**...

†[مولانا عبید اللہ خاں اعظمی :

۴۵ منٹ ہو گئے ہیں، ۴۵ منٹ .... (مداخلت).... اکسٹرا ٹائم دیا گیا ہے، پارٹیوں کا سمے بڑھانے کے بعد ہی ۴۷ منٹ اکسٹرا ٹائم دیا گیا ہے۔ (مداخلت)

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): He may lay it on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : आप खत्म करिये। What about your last sentence ?

SHRI JAGMOHAN : I will make only one or two more points. I entirely agree with Mr. Dipen Ghosh. I will place a copy of the book on the Table of the House. It is for the information of the House that I am saying this. Let us go back to 1952 or so when this sort of a suggestion was made. I would request you to consider that, What does it mean ? This should be specified. You don't want any financial integration with India. You want to live within your own resources. This question has not been answered and if you go back to such a situation, Article 356 was not there in Kashmir. You did not have so many other things in Kashmir. What do you want ? You want a one-way traffic.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : We want Sarkaria Commission.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : मिस्टर वाइस-चयरमैन सर, आपने अपनी बेपनाह फरियादियों का खाता बढ़ाकर हमारे पेश मुकर्रर मिस्टर जगमोहन साहब को 45 से 50 मिनटों का समय दिया है। मैं चाहूंगा कि कम से कम इतना टाइम मुझे भी जरूर मिले।

†[مولانا عبیداللہ خاں اعظمی :

مسٹر وائس چیر مین سر - آپنے اپنی بےپناہ فریادیوں کا کھاتا بڑھاکر ہمارے پیش مقرر مسٹر جگ موہن صاحب کو ۴۵ منٹ سے ۵۰ منٹوں کا سمے دیا ہے - میں چاہوں گا کہ کم سے کم اتنا ٹائم مجھے بھی ضرور ملے -]

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): आप पहले शुरू तो कीजिये।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : कश्मीर के फूलों का लहू देखने वालों, हर आंख में यह फूल उतर जायेगा इक दिन, कलियों को मसलने का तरीका जो न बदला, यगजहती का दाना भी बिखर जायेगा इक दिन।

सारा कश्मीर जल रहा है, कश्मीर सुलग रहा है, कश्मीर के नौजवान मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, यह सभी जानते हैं। लेकिन अभी तक न किसी ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की और न ही कश्मीरियों के लिये सकून की तड़प महसूस की और न ही किसी ने कश्मीरी नौजवानों को रास्ता दिखाने की जद्दोजहद की। इसकी वजह यह नहीं है कि किसी को हमदर्दी नहीं है, वजह यह नहीं है कि मुल्क के एक हिस्से में फैली हुई तबाही से किसी को दुख नहीं है। हर एक तास्सुब की ऐनक से कश्मीर के मसले को देख रहा है या फिर गर जानिबदारी का तक करके और किसी एक ग्रुप की तरफदारी करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो हुकूमते हिन्द या सक्योरिटी फोसस पर नुक्ता-चीनी करके हिन्दुस्तान के खिलाफ सरगर्मी करार देते हैं और कुछ एसे भी हैं जो सब कुछ जानते हुये भी खामोश रहते हैं। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि

‡[Transliteration in Arabic Script]

[मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी]

कश्मीर खंडहर बन रहा है और कश्मीर बेमौत मर रहा है । आज कश्मीर की समस्या, कश्मीर के मसले पर मुखतलिफ पार्टियों के मुखतलिफ नजरियात आ रहे हैं । लेकिन हम सबों की एक राय है और यह तमामतर हिन्दुस्तानियों की राय कहलाती है कि कश्मीर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है । हिन्दुस्तान का एक अटूट अंग है । कश्मीर को बचाने के लिए और कश्मीर में जम्हूरियत और सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए कश्मीरी आवाम को बचाना भी निहायत जरूरी है । कश्मीर में पत्थरों पर हुकूमत नहीं की जाएगी । कश्मीर में फूलों पर आर्डर नहीं चलाया जाएगा । कश्मीर में झरनों के ऊपर दफात नाफिस नहीं की जाएगी । कश्मीर में इन्सानों को साथ लेकर चला जाएगा । जिन इन्सानों को, बेगुनाह लोगों को गोलियों और संगीनों के जरिये मसला गया, कुचला गया, मारा गया, पीटा गया । इसके बावजूद अपने बजूद, अपने करेक्टर की सफाई देने वाले सफाई दे रहे हैं । मुझे तो इस मौके पर यह कहना है कि— हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।

मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि कश्मीर में यह हालात क्यों पैदा हुए । कश्मीर में दहशतगर्दी हो, हमें उसका भी खण्डन करना चाहिये । कश्मीर में हिन्दुस्तान से अलग होने की बात हो रही हो तो हमें जम कर के मजम्मत करनी चाहिये । कश्मीरी आवाम को हिन्दुस्तान के साथ जोड़ने के लिए भी निहायत जरूरी है कि हम संजीदा माहौल पैदा करें और संजीदगी के साथ ऐसा रास्ता निकालें, उनका खोया हुआ एहतमाद वापिस लाया जाए, दहशतगर्दी से वहां के आवाम को नफरत करवाई जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस रास्ते के जरिये से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे । मगर कश्मीर के मसले को हमेशा राजनीतिक सलीब पर चढ़ा कर फांसी दी जाती रही है । हर पार्टी अपने मफाद के लिए कश्मीर के वजूद से खेलती रही है, कश्मीरियों को जुल्मो-जबर की चक्की में पीसती रही है और कश्मीरियों ने अपने आपको हिन्दुस्तान के साथ जिन उम्मीदों को लेकर इलहा किया था आज कश्मीर का कामन इन्सान यह महसूस करता है कि उसके साथ धोखा किया गया । दूसरी तरफ लगातार यह कोशिश होती रही भारत सरकार की तरफ से कि सूबा कश्मीर की खुद मुखतारी को कम किया जाए और उसके अन्दरूनी मामलात में मदाखलत की जाए । आईन की दफा 370 पर जो इतना बड़ा हंगामा पूरे मुल्क में किया जा रहा है और करवाया जा रहा है ईमानदारी का चालीसवां हिस्सा भी अगर बतौरे खैरातोजकात किसी पार्टी के अन्दर अगर मौजूद हो तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि दफा 370 को तोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक माहौल बनाया जा रहा है । शिमला में बी०जे०पी० की हकूमत है । हिमाचल प्रदेश में भी सम्पत्ति नहीं खरीदी जा सकती है । बीदर में भी इस तरह का कानून बनाया हुआ है । मराठवाड़ा में भी इस तरह का कानून है । आखिर वहां इस तरह की मोहिम क्यों नहीं चलाई जाती है या वहां के मसायल के लिए यह बातें क्यों नहीं की जाती हैं ? इस तरह की दो तरफा एनक लगा कर हिन्दुस्तान के लोगों को एक्सप्लायट करते हुए लोगों के धार्मिक और राजनीतिक जजबातों से खेल कर हर पार्टी अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही है । मैं कहना चाहता हूं कि समस्या को समस्या समझ कर, राजनीति समझ कर नहीं हल करना चाहिये । पार्टियों से ऊपर उठ कर मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क की अजमत के लिए, मुल्क के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने वजूद की कुर्बानी देकर भी अगर हिन्दुस्तान के बिखरे हुए दलों को इकट्ठा किया जा सकता है तो भेदभाव भुला कर आपसी इत्तेहाद के साथ तमामतर लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाना चाहिये । मैं कहता हूं कि दफा 370 अब तक सिर्फ दिखावे के लिए ही इस्तेमाल हुई है ।

उससे कश्मीरियों को कौन सा फायदा पहुंचा है। वहां के लोगों की जुबान वहां के कल्चर और वहां के मजहबी फिकरोफन के साथ हमेशा खिलवाड़ किया गया और उनको कनजोर बनाने की कोशिश की गई। कश्मीरियों के साथ तरक्की के जो वायदे किये गये थे वह भी पूरे नहीं किये गये और वहां जो भी पैसा जाता है उनकी तरक्की के लिए वह पैसा भी उनकी तरक्की की राह में लगता हुआ दिखाई नहीं देता। उनके साथ हिन्दुस्तान के शहरियों जैसा सलूक भी नहीं हो रहा है। जैसे फौज वगैरह का इस्तेमाल हमेशा दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है मगर जब भारतीय और हिन्दुस्तानी नागरिकों के लिए फौज का इस्तेमाल किया जाए तो क्या शक्लो शुबहात के बादल नहीं उठेंगे, क्या शक्लो नफरत का पानी नहीं बरसेगा? फौज और पुलिस को मजालिम करने के लिए घरों और दुकानों में आग लगाने के लिए औरतों की आबरू रेजी करने के लिए तकरीबन कश्मीर में मुकम्मल छूट दी गई है। मेरे पेशरोमुकर्रिर ने जिस तरह से वहां फिरकापरस्तों और अलगाववादियों की संख्या दी है बेहतर तो यह होता ईमानदारी का तकाजा यह था कि वह यह भी बता देते कि किस तरह से वहां की औरतों की इज्जत लूटी गई, फोर्स के लोगों ने किस तरह से वहां के बेकसूर जानों को मारा है, क्या वहां सारी चीज दहशतपसंदी का रास्ता नहीं पैदा करतीं, क्या यह सारी चीजें दहशतपसंदी के लिए शुबहात की अलामत नहीं बनतीं? आर्म्ड फोर्सेज नहीं हमारे यहां अखबारों में ये बात आ चुकी हैं कि किस तरह से आबरूरेजी फोर्सेज के जरिये हुई है। अखबारात में हमारे यहां ये पूरी तफसीलात छपी है कि किस तरह से औरतों घरों से निकाली गयीं और उनकी आबरूरेजी की गयी। अगर यही बात है तो उन अखबारात को उठाइये और प्रेस से बात कीजिए। मैं तो वह बात कह रहा हूं जो मुझे प्रेस के माध्यम से मिली हैं मेरे पास रिकार्ड भी है। मैं उसका सबूत भी रखता हूं। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि इस तरह की जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं इन गड़बड़ियों में अगर हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे तो इससे काश्मीर का मसला हल नहीं होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कल हमारे मोहतरम सिकन्दर बख्त साहब ने जो हमारे मुअज्जिज मेम्बर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं एक बात कही थी कि काश्मीर का मसला 1947 से बिगाड़ा गया और काश्मीरी लीडर काश्मीर से पाकिस्तान जाते रहे। उन्होंने 1947 से मुसलसल रंग बदले। कभी अमानुल्ला खान से मिले, कभी सरदार अब्दुल कयूम से मिले। मेरे भाई अगर आप बुरा न माने तो मैं यह कहूं कि काश्मीरी लीडरों का अगर यह जूमं था कि वे अमानुल्ला खान से मिले, सरदार अब्दुल कयम से मिले तो अभी आपके आर० के० मलकानी पाकिस्तान गये थे। वे भी अमानुल्ला खान से मिलकर आये, सरकार अब्दुल कयूम से मिलकर आये और उसके बाद आपने एकता यात्रा निकाली। मैं तो इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि आप लोगों ने जे०के०एल०एफ० के साथ गठजोड़ कर रखा है। जे०के०एल०एफ० से आपने कहा कि काश्मीर में एंटर करो और हम एकता यात्रा निकालते हैं। काश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की कोशिश की। आपका यह मानना है कि जब तक काश्मीर हिन्दुस्तान से अलग नहीं होगा हमारा हिन्दू राष्ट्र का सपना अपना नहीं हो सकता और उसके लिए आपने जे०के०एल०एफ० वालों से गठजोड़ करके हिन्दुस्तान से काश्मीर को अलग थलग करने का नापाक खेल किया। आप बात कर रहे हैं एकता यात्रा की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जोशी साहब ने अपनी एकता यात्रा के दौरान एक बयान दिया था। वह भी मेरे रिकार्ड में है। उन्होंने कहा था कि हम काश्मीर को हिन्दुस्तान के साथ जोड़ेंगे। इसका क्या मतलब है। काश्मीर हिन्दुस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ। काश्मीर पाकिस्तान में है, इसका क्या मतलब हुआ। काश्मीर का हिन्दुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि हम काश्मीर को वापस लाएंगे और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि काश्मीर भारत माता का अटूट अंग है, यह दोहरी पालिसी चलाकर आपने मुल्क को तबाह और बरबाद कर दिया है।

[मौलाना ओबैदुल्ला खां आजमी]

दूसरी एक और बात कहूंगा। कल सिकन्दर बख्त जी ने कहा था कि वहां कुछ दहशतपसंद जमाते हैं जो एक मजहब के नाम से अपने अपने आर्गेनाइजेशंस का नाम रखे हुए हैं जैसे हिजबुल मुजाहिदीन जैसे अल उमर। एक बात मैं चाहता हूं। बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने और किसी भी मजहब के नाम से अगर ऐसे आर्गेनाइजेशन धार्मिक देवताओं के नाम से बनते हैं जो देश की यकजहदी के लिए खतरा बनते हैं जो उसका हम तमाम हिंदुस्तानियों को खंडन करना चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अल उमर तंजीम बनी है काश्मीर में, हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम बनी है काश्मीर में उन्होंने इस्लाम के नाम पर और मजहब के धार्मिक नेताओं के नाम पर अपनी आर्गेनाइजशंस का नाम रखा है य बी०जे०पी० वाले जिस बजरंग दल की सरपस्ती कर रहे हैं यह किसके नाम से बनी है, जिस दुर्गा वाहिनी की सरपरस्ती कर रहे हैं यह किसके नाम से बनी है, जिस शिव सेना की सरपरस्ती कर रहे हैं यह किसके नाम से बनी है। क्या शिवजी के नाम से हिंदुस्तान के हिंदुओं में उग्रवाद फैलाना देश के साथ वफादारी है, क्या दुर्गा जी के नाम से हिंदुस्तान के लोगों में दहशतपसंदगी करना देश के साथ वफादारी है और क्या बजरंग जी के नाम से हिंदुस्तान के अंदर दहशतपसंदगी करना देश के साथ वफादारी है। यही वे तरीकेकार हैं जिनसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में उग्रवाद को बढ़ावा मिलता है। उग्रवाद ने बी०जे०पी० की कोख से जन्म लिया है। यही नतीजा है कि आज पूरा देश छिन्न भिन्न होकर रह गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक धार्मिक राजनीति से ऊपर उठकर आप बात नहीं कीजिएगा जब तक आप बेदर्दी के साथ सेक्यूलीरिज्म की बका व तरद्दुद की बात नहीं कीजिएगा उस वक्त तक मुल्क में वहशतों की घटनाएं उठती रहेंगी और नफरतों का पानी बरसता रहेगा मेरी आपसे गुजारिश है कि काश्मीर के मसले को पार्टी की ऐनक लगाकर मत देखिए, भारत के इतिहास की ऐनक लगाकर देखिए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का चश्मा लगाइये और उस चश्मे से देखिए तभी हिन्दुस्तान के साथ काश्मीर को हम उज्जवल भविष्य दे सकेंगे आगे बढ़ा सकेंगे। आज सदर राज की बात आई है। हमारी बदनसीबी है कि हम फिर 6 महीने के लिए सदर राज की तौफीक करने जा रहे हैं। यह जम्हूरी मुल्क में एक बड़ी तकलीफदेह बात है कि हमेशा सदर राज रहे, हमेशा मार्शल ला का माहोल रहे। होना तो यह चाहिए था कि जिस तरह पंजाब में इलेक्शन हुआ है उसी तरह से काश्मीर में भी इलेक्शन करवाया गया होता। चन्द्रशेखर जी के जमाने का एक वाक्या मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इसी हाऊस में चन्द्र शेखर सरकार ने कहा था कि असम के हालात कश्मीर से ज्यादा बदतर और खराब हो चुके हैं। इसलिए असम में जब सरकार ने महसूस किया, बयान दिया कि असम के हालात कश्मीर से ज्यादा खराब हो चुके हैं, उसकी वजह क्या थी ? उसकी वजह थी उलफा आतंकवाद। मगर उसके बावजूद असम में इलैक्शन करवाये गये। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि आज सदर राज की तौसी के लिये यहां बिल पेश किया जा रहा है, जब गवर्नमेंट यहां एक एलान कर चुकी कि असम में हालात कश्मीर से ज्यादा बदतर हैं, इसके बावजूद असम में इलैक्शन करवाये गये, कश्मीर में इलैक्शन क्यों नहीं करवाये जा रहे हैं ?

पंजाब के हालात इतने खराब थे, पंजाब में इलैक्शन क्यों करवाये गये ? कश्मीर में इलैक्शन क्यों नहीं करवाये जाते। टैरोरिज्म हमने पंजाब का भी आठ साल से देखा है, मगर शुक्र कीजिए कि पंजाब के टैरोरिज्म में यह देखने को मिला कि बसों से लोगों को उतार-उतार करके मारा गया, एक तबके के लोगों को मरा गया, एक फिरके के लोगों को मारा गया। इनसान इनसान है। उसको धर्मों में बांट करके जानवर मत बनाइये। कहीं भी कोई इंनसान मारा जाता है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। अफसोस के साथ शर्म से अपने सर को झुका देना चाहिए।

हिंदू हो कि मुसलमान, वह हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हिंदुस्तान की तामीर का एक करेक्टर है और उसकी हिफाजत करना जातपात से उठ कर यह हमारा धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। इसी नीति के साथ अगर हम भारत माता को इज्जत और वकार

देना चाहते हैं, तो हिंदू, मुसलिम, सिख ईसाई से ऊपर उठ कर एक सच्चे हिंदुस्तान की हैसीयत से हिंदुस्तान के सारे सूबों को देखिये और उनमें बढी हुई तमाम तबाहियों को खत्म करते हुए, आबादी और विकास की तरफ इस देश को ले जाइये ।

निहायत अफसोस के साथ मैं सदारती तौसी की हिमायत कर रहा हूं, मगर उम्मीद भी करता हूं कि अगला दौर छः महीने में ऐसा किया जाना चाहिए कि कश्मीर में इलैक्शन का माहौल बने, अवामी नुमांइदों के हाथ कश्मीर को दे दिया जाए ताकि उनके जरिए जिस तरह से पंजाब में हमने जम्हूरियत की बहाली के लिए कदम उठाया है, कश्मीर में भी जम्हूरियत और स्वतंत्रता के लिए कदम उठाये और कश्मीर भी मुस्तकबिल में हिंदुस्तान के साथ जुड़ कर दूसरे सूबों की तरह से कामयाबी की राह पर गामजन हो सके ।

शुक्रिया ।

†[مولانا عبیداللہ خاں اعظمی :

کشمیر کے پھولوں کا لہو دیکھنے والوں -
ہر آنکھ میں یہ خون اتر جائیگا اک دن-
کلیوں کو مسلنے کا طریقہ جو نہ بدلا
یکجہتی کا دانا بھی بکھر جائیگا اک دن-

سارا کشمیر جل رہا ہے - کشمیر سلگ رہا ہے کشمیر کے نوجوان کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے - یہ سبھی جانتے ہیں - لیکن ابھی تک نہ کسی نے اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کی اور نہ ہی کشمیریوں کیلئے تڑپ محسوس کی اور نہ ہی کسی نے کشمیری نوجوان کو راستہ دکھانے کی جدو جہد کی - اسکی وجہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہمدردی نہیں ہے - وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک کے ایک حصہ میں پھیلی ہوئی تباہی سے کسی کو دکھ نہیں ہے - ہر ایک تعصب کی عینک سے کشمیر کے مسئلے کو دیکھ رہا ہے - یا پھر غیر جانبداری ترک کرکے اور کسی ایک گروپ کی طرفداری کرتے ہیں کئی ایسے بھی ہیں جو حکومت ہند یا سیکورٹی فورسیز کی نکتہ چینی کرکے ہندوستان کے خلاف سرگرمی قرار دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں ، اسکا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کشمیر کہنڈر بن رہا ہے اور کشمیر بےموت مر رہا ہے- آج کشمیر کی سمسیا کشمیر کے مسئلے پر مختلف پارٹیوں کے مختلف نظریات آ رہے ہیں - لیکن ہم سب کی ایک رائے ہے اور یہ تمام تر ہندوستانیوں کی رائے کہلاتی ہے کہ کشمیر ہندوستان کا ایک حصہ ہے - ہندوستان کا یک اٹوٹ انگ ہے - کشمیر کو بچانے کیلئے کشمیر میں جمہوریت کو اور سیکولرزم کو برقرار رکھنے کیلئے کشمیری عوام کو بچانا بھی نہایت ضروری ہے - کشمیر میں پتھروں پر حکومت نہیں کی جائیگی- کشمیر میں انسانوں کو ساتھ لیکر چلا جائیگا- جن انسانوں کو-

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

بے گناہ لوگوں کو گولیوں اور سنگینوں کے ذریعہ مسلا گیا۔ کچلا گیا۔ مارا گیا۔ پیٹا گیا اس کے باوجود اپنے وجود۔ اپنے کیرکٹر کی صفائی دینے والے صفائی دے رہے ہیں مجھے اس موقع پر یہ کہنا ہے کہ۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر میں یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ کشمیر میں دہشت گردی ہو۔ ہمیں اس کا بھی کھنڈن کرنا چاہیے۔ کشمیر میں ہندوستان سے الگ ہونے کی بات ہو رہی ہو تو ہمیں جم کر کے مذمت کرنی چاہیے۔ کشمیری عوام کو ہندوستان کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم سنجیدہ ماحول پیدا کریں اور سنجیدگی کے ساتھ ایسا راستہ نکالیں۔ ان کا کھویا ہوا اعتماد واپس لایا جائے۔ دہشت گردوں سے وہاں کے عوام کو نفرت کروائی جائے۔ دہشت گردی کے خلاف ایسا راستہ نکالا جائے جس راستہ کے ذریعہ سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مگر کشمیر کے مسئلہ کو ہمیشہ راجنیتک مہلب پر چڑھا کر پھانسی دی جاتی رہی ہے۔ ہر پارٹی اپنے مفاد کے لیے کشمیر کے وجود سے کھیلتی رہی ہے۔ کشمیریوں کو ظلم و جبر کی چکی میں پیستی رہی ہے اور کشمیریوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ جن امیدوں کو لے کر الحاق کیا تھا آج کشمیر کا کامن انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ دوسری طرف لگاتار یہ کوشش ہوتی رہی بھارت سرکار کی طرف سے کہ صوبہ کشمیر کی خود مختاری کو کم کیا جائے اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جائے۔ آئین کی دفعہ ۳۷۰ پر جو اتنا بڑا ہنگامہ پورے ملک میں کیا جا رہا ہے۔ اور کروایا جا رہا ہے۔ ایمانداری کا چالیسواں حصہ بھی اگر بطور خیرات و زکوٰۃ کسی پارٹی کے اندر اگر موجود ہو تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دفعہ ۳۷۰ کو توڑنے کے لیے کنیا کماری سے کشمیر تک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ شملہ میں بی۔ جے۔ پی۔ کی حکومت ہے ہماچل پردیش میں بھی سمپتی نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ بیدر میں بھی اس طرح کی مہم کیوں نہیں چلائی جاتی۔ یا وہاں کے مسائل کیلئے یہ باتیں کیوں نہیں کی جاتیں۔ اس طرح کی دوطرفہ عینک لگا کر ہندوستان کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے لوگوں کے دھارمک اور راج نیتک جذبات

سے کھیل کر ہر پارٹی اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سمسیا کو سمسیا سمجھ کر۔ راج نیتی سمجھ کر نہیں حل کرنا چاہیے۔ پارٹیوں سے اوپر اٹھ کر ملک کے مفاد کے لیے ملک کی عظمت کے لیے۔ ملک کے اتحاد بھروسے کے لیے اپنے وجود کی قربانی دے کر بھی اگر ہندوستان کے بکھرے ہوئے دانوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو بھید بھاؤ بھلا کر آپسی اتحاد کے ساتھ تمام تر لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ دفعہ ۳۷۰ اب تک صرف دکھاوے کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے۔ اس سے کشمیریوں کو کون سا فائدہ پہنچا ہے۔ وہاں کے لوگوں کی زبان وہاں کے کلچر اور وہاں کے مذہبی فکر و فن کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ کیا گیا اور ان کو کمزور بنانے کی کوشش کی گئی۔ کشمیریوں کے ساتھ ترقی کے جو وعدے کئے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں کئے گئے۔ اور وہاں جو بھی پیسہ جاتا ہے۔ ان کی ترقی کیلئے وہ پیسہ بھی ان کی ترقی کی راہ میں لگتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے ساتھ ہندوستان کے شہریوں جیسا سلوک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے فوج وغیرہ کا استعمال ہمیشہ دشمنوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ مگر جب بھارتیہ اور ہندوستانی ناگرکوں کے لیے فوج کا استعمال کیا جائے تو کیا شک و شبہات کے بادل نہیں اٹھیں گے۔ کیا شک و نفرت کا پانی نہیں برسے گا۔ فوج اور پولیس کو مظالم کرنے کے لیے گھروں اور دکانوں میں آگ لگانے کے لیے عورتوں کی آبرو ریزی کرنے کے لیے تقریباً کشمیر میں مکمل چھوٹ دی گئی ہے۔ میرے پیش رو مقرر نے جس طرح سے وہاں فرقہ پرستوں اور الگاؤ وادیوں کی سنکھیادی ہے بہتر تو یہ ہوتا ایمانداری کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ یہ بھی بتا دیتے کہ کس طرح سے وہاں کی عورتوں کی عزت لوٹی گئی۔ فورس کے لوگوں نے کس طرح سے وہاں کے بے قصور جوانوں کو مارا ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں دہشت پسندی کا راستہ نہیں پیدا کرتی۔ کیا یہ ساری چیزیں دہشت پسندی کا راستہ نہیں پیدا کرتیں۔ کیا یہ ساری چیزیں دہشت پسندی کیلئے شبہات کی علامت نہیں بنتیں۔

آرمڈ فورسیز نہیں ہمارے یہاں اخباروں میں یہ باتیں آچکی ہیں کہ کس طرح سے آبرو ریزی فورسیز کے ذریعے ہوئی ہے۔ اخبارات میں ہمارے یہاں یہ پوری

تفصیل چھپی ہے۔ کہ کس طرح سے عورتیں گھروں سے نکالی گئیں۔ اور انکی آبروریزی کی گئی۔ اگر یہی بات ہے تو ان اخبارات کو اٹھائیے اور پریس سے بات کیجئے۔ میں تو وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو پریس کے مادھیم سے ملیں ہیں۔ میرے پاس ریکارڈ بھی ہے۔ میں اس کا ثبوت بھی رکھتا ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں ان گڑبڑیوں میں اگر ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گے تو اس سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔

میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کل ہمارے محترم سکندر بخت صاحب نے جو ہمارے معزز ممبر ہیں۔ ہمارے سینئر لیڈر ہیں۔ ایک بات کہی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ ۱۹۴۷ میں بگاڑا گیا۔ اور کشمیری لیڈر کشمیر سے پاکستان جاتے رہے۔ انھوں نے ۱۹۴۷ سے مسلسل کئی رنگ بدلے۔ کبھی امان اللہ خاں سے ملے۔ کبھی سردار عبدالقیوم سے ملے۔ میرے بھائی اگر برا نہ مانیں تو میں یہ کہوں کہ کشمیری لیڈروں کا اگر یہ جرم تھا کہ وہ امان اللہ خاں سے ملے۔ سردار عبدالقیوم سے ملے تو ابھی آپ کے آر۔ کے۔ ملکانی پاکستان گئے تھے۔ وہ بھی امان اللہ خاں سے مل کر آئے۔ سردار عبدالقیوم سے مل کر آئے۔ اور اسکے بعد آپ نے ایکتا یاترا نکالی۔ میں تو اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں نے جے۔ کے۔ ایل۔ ایف۔ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ جے۔ کے۔ ایل۔ ایف سے آپ نے کہا کہ کشمیر میں انٹر کرو اور ہم ایکتا یاترا نکالتے ہیں۔ کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا یہ ماننا ہے کہ جب تک کشمیر ہندوستان سے الگ نہیں ہوگا ہمارا ہندو راشٹر کا سپنا اپنا نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے آپ نے جے۔ کے۔ ایل۔ ایف۔ والوں سے گٹھ جوڑ کر کے ہندوستان سے کشمیر کو الگ تھلگ کرنے کا ناپاک کھیل کیا۔ آپ بات کر رہے ہیں ایکتا یاترا کی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرلی منوہر جوشی صاحب نے اپنی ایکتا یاترا کے دوران ایک بیان دیا تھا۔ وہ بھی میرے ریکارڈ میں ہے۔ انھوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ جوڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے۔ کشمیر ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا۔ کشمیر ہندوستان میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا۔ کشمیر کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو واپس

لائیں گے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بھارت ماتا کا اٹوٹ انگ ہے۔ یہ دوہری پالیسی چلاکر آپ نے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔

دوسری ایک اور بات کہوں گا۔ کل سکندر بخت جی نے کہا تھا کہ وہاں کچھ دہشت پسند جماعتیں ہیں جو ایک مذہب کے نام سے اپنے اپنے آرگنائزیشنس کا نام رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے حزب المجاہدین جیسے العمر۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا تھا انھوں نے اور کسی بھی مذہب کے نام سے اگر ایسے آرگنائزیشنس۔ دھارمک دیوتاؤں کے نام سے بنتے ہیں جو دیش کی یکجہتی کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ تو اس کا ہم تمام ہندوستانیوں کو کھنڈن کرنا چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ العمر تنظیم بنی ہے۔ کشمیر میں حزب المجاہدین تنظیم بنی ہے۔ کشمیر میں انھوں نے اسلام کے نام پر اور مذہب کے دھارمک نیتاؤں کے نام اپنی آرگنائزیشنس کا نام رکھا ہے یہ بی۔ جے۔ پی۔ والے جس بجرنگ دل کی سرپرستی کر رہے ہیں یہ کس کے نام سے بنی ہے۔ جس درگا واہنی کی سرپرستی کر رہے ہیں یہ کس کے نام سے

بنی ہے - جس شیو سینا کی سرپرستی کر رہے ہیں یہ کس کے نام سے بنی ہے - کیا شیوا جی کے نام سے ہندوستان کے ہندوؤں میں اکروات پھیلانا دیش کے ساتھ وفاداری ہے؟ کیا درگا جی کے نام سے ہندوستان کے لوگوں

میں دہشت پسندی کرنا دیش کے ساتھ وفاداری ہے اور کیا بجرنگ جی کے نام سے ہندوستان کے اندر دہشت پسندی کرنا دیش کے ساتھ وفاداری ہے۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جن سے ملک کے دوسرے حصّوں میں اگر واد کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اگر واد نے بی۔ جے۔ پی۔ کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج پورا دیش چھن بھن ہو کر رہ گیا ہے۔ اسلئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک دھارمک راج نیتی سے اوپر اٹھ کر آپ بات نہیں کیجئے گا جب تک آپ بیدردی کے ساتھ سیکولرازم کی بقا" و تردد کی بات نہیں کیجئے گا۔ اس وقت تک ملک میں وحشتوں کی گھٹائیں اٹھتی رہے گی۔ اور نفرتوں کا پانی برستا رہے گا۔ میری آپ سے گذارش ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو پارٹی کی عینک لگاکر مت دیکھئے۔ بھارت کے اتہاس کی عینک لگاکر دیکھئے۔ ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا کا چشمہ لگائیے اور اس چشمے سے دیکھئے تبھی ہندوستان کے ساتھ کشمیر کو اٹوٹ بھوشیے دے سکینگے۔

آگے بڑھا سکیں گے۔ آج صدر راج کی بات آئی ہے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم پھر چھ مہینے کے لیے صدر راج کی توثیق کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جمہوری حقوق ملک میں ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمیشہ صدر راج رہے۔ ہمیشہ مارشل لاء کا ماحول رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح پنجاب میں الیکشن ہوا۔ اس طرح سے کشمیر میں بھی الیکشن کروایا گیا ہوتا۔ چندر شیکھر جی کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اسی ہاؤس میں چندر شیکھر سرکار نے کہا تھا کہ آسام کے حالات کشمیر سے زیادہ بدتر اور خراب ہو چکے ہیں۔ اس لیے آسام میں جب سرکار نے محسوس کیا بیان دیا کہ آسام کے حالات کشمیر سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ تھی الفا آئی کو اڈ۔ مگر اس کے باوجود آسام میں الیکشن کروائے گئے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آج صدر راج کی توثیق کے لیے یہاں بل پیش کیا جا رہا ہے۔ جب گورنمنٹ یہاں ایک اعلان کر چکی ہے کہ آسام میں حالات کشمیر سے زیادہ بدتر ہیں۔ اس کے باوجود آسام میں الیکشن کروائے گئے۔ کشمیر میں الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے ہیں۔

پنجاب کے حالات اتنے خراب تھے۔ پنجاب میں الیکشن کروائے گئے۔ کشمیر میں الیکشن کیوں نہیں کروائے جاتے۔ ٹیر ورزم ہم نے پنجاب میں بھی آٹھ سال سے دیکھا ہے۔ مگر شکر کیجئے کہ ٹیر ورزم میں یہ دیکھنے کو ملا کہ بسوں سے لوگوں کو اتار اتار کر کے مارا گیا۔ ایک طبقے کے لوگوں کو مارا گیا۔ ایک فرقے کے لوگوں کو مارا گیا۔ انسان انسان ہے۔ اس کو دھرموں میں بانٹ کر کے جانور مت بنائیے۔ کہیں بھی کوئی انسان مارا جاتا ہے۔ ہمیں اس کی تنداگری چاہیے۔ افسوس کے ساتھ شرم سے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے ہندو ہو کہ مسلمان۔ وہ ہندوستانی ہے۔ ہندوستان کا ایک حصہ ہے۔ ہندوستان کی تعمیر کا ایک کریکٹر ہے۔ اور اسکی حفاظت ذات پات سے اٹھ کر۔ یہ ہمارا دھرم اور کرتوے ہونا چاہیے۔ اسی نیتی کے ساتھ اگر ہم بھارت ماتا کو عزت اور وقار دینا چاہتے ہیں تو ہندو مسلم سکھ عیسائی سے اوپر اٹھ کر

ایک سچے ہندوستانی کی حیثیت سے ہندوستان کے سارے صوبوں کو دیکھیے۔ اور انھیں بڑھی ہوئی تمام تباہیوں کو ختم کرتے ہوئے آبادی اور روزگار کی طرف اس دیش کو لے جائیے۔

نہایت افسوس کے ساتھ میں ہر راوتی توسیع کی حمایت کر رہا ہوں۔ مگر امید بھی کرتا ہوں کہ اگلا دور چھ مہینے میں ایسا کیا جانا چاہیے۔ کہ کشمیر میں الیکشن کا ماحول بنے۔ عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں کشمیر کو دے دیا جائے۔ تاکہ ان کے ذریعے جس طرح سے پنجاب میں ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے قدم اٹھایا ہے کشمیر میں بھی جمہوریت اور سوتنترتا کے لیے قدم اٹھائیں۔ اور کشمیر بھی مستقبل میں ہندوستان کے ساتھ جوڑ کر دوسرے صوبوں کی طرح کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ شکریہ۔

"ختم شد"

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : I have to make an announcement.

SHRI DEPEN GHOSH : I have to make one.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Your impatience is running ahead of the schedule. I have to make an announcement.

This morning some hon. Members raised points about the papers laid by the Minister of Finance yesterday. The Minister of Finance will come to the House at 5 P.M. today to clarify the matter.

Mr. Vincent. Take only two or three minutes.

SHRI M. VINCENT (Tamil Nadu) : The affairs of Jammu and Kashmir remain a sensitive issue in all spheres. To bring the so called militants of Kashmir into the mainstream of Indian democracy it needs to infuse confidence in them by strengthening our intelligence activities and propaganda. It is advisable that the Government gradually but expeditiously should re-introduce people of the same State in the bureaucratic and administrative posts. Incidentally, this bring back the confidence of the people of Kashmir.

Secondly, the Delimitation Commission should be given a time bound direction to complete the work of fresh delimitation. This would enable to advance the date of election in Jammu and Kashmir.

The dangerous dimension of the problem is the support to terrorists by Pakistan. It has been abetting terrorism in Kashmir all along and now it has openly declared it.

I congratulate the Prime Minister for his assertion that India would not compromise with even an inch of our land at any cost. Our Defence Minister, Mr Pawar, deserves a loud applause for declaring that Pakistan would be taught a fitting lesson if it did not stop poking its nose in our internal affairs.

A group of anti-social elements are playing into the hands of Pakistan. Therefore, the Government must take effective steps to put an end to Pakistan's sinister designs.

[Shri M. Vincent]

Sir, the constitution of a 14 member Council to advise the Governor on political and economic matters is a right step. This will pave way for creating an atmosphere of hope and security in the State.

Elections in Punjab were successfully conducted and a popular people's Government has been installed against terrorism and successionist activities. In the same manner I appeal that elections in Jammu and Kashmir should be conducted to bring the entire country to have elected popular Governments.

Thank you.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जगमोहन जी ने जो दो-तीन बातें कही हैं उसकी रोशनी में समस्या का समाधान तलाशना चाहिए। लेकिन इनकी बात का एक अंश मुझको इतना बेतरतीब लगा, उल्टा लगा... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी०ठाकुर) : आप अपनी बात कहिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : इन्होंने बात कही है और मूल समस्या का समाधान है। इन्होंने यह कहा कि जब तक वहां के खराफाती लोगों का सफाया पूरे तौर पर नहीं किया जाता तब तक यह काश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होगा और वहां स्टेट अथारिटी को रेस्टोर नहीं किया जा सकता है । यह अलफाज इन्होने कहा है । एक यह कहा और दूसरी बात... **(व्यवधान)** सस्टेन, यस सर। आपने अंग्रेजी में कहा, मैं उसका हिन्दी में तर्जुमा कर रहा हूं।.. **(व्यवधान)** आप परजिंग शब्द नहीं यूज किया है, यह बात अलग है। लेकिन आपने कहा कि उनका पूरे तौर पर सफाया होना चाहिए। नंबर दो कहा कि शुरू से ही काश्मीर, जब से भारत में काश्मीर का विलय हुआ है तब से काश्मीर धोखा-धड़ी की चाल चलता रहा है। सह आपने दो बातें कही हैं! यह दूसरी बात के समर्थन में आपने डाकूमेंट्स भी दिखाना चाहा, कुछ चिट्ठी भी पढ़ी। सी. आर. चिनार जो एक आटोग्राफी है शेख साहब की उसकी कुछ पंक्तियां भी आपने कोट की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम बहुल काश्मीर एरिया उस पर हमने आक्रमण नहीं किया। आक्रमण करके अपने में नहीं मिलाया। वह हमारा हिस्सा नहीं था आजादी तक, उसने स्वयं, उसके पास यह लिबर्टी थी काश्मीर के पास कि वह पाकिस्तान में भी अपने को मिला सकता था और वह हिन्दुस्तान में भी अपने को मिला सकता था। लेकिन काश्मीर के हुक्मरानों ने स्वेच्छा से चुना कि हम भारत के साथ रहेंगे, भारत के साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था होगी। मुसलमान का राज्य नया बना हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम राज बने इस सिद्धांत पर पाकिस्तान बना था। उसके साथ पाकिस्तानी हुक्मरान वह मुस्लिम बहुल एरिया के लोग और उसके हुक्मरानों ने तय किया कि हम मुस्लिम राष्ट्र के साथ नहीं जायेंगे, हम भारत के साथ जायेंगे यह एक बड़ी अच्छी चीज थी। लेकिन आपने यह बात कह दी तो पूरे सेकुलरिज्म के ढांचे पर चोट पहुंचा दी। जो भारत के सैकुलरिज्म का, भारत में धर्म निरपेक्षता का रूप था उसको खंडित करने की कोशिश आपने अपने बयान से की है। जब आपकी दृष्टि ही ऐसी है कि शुरू से.....

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : अब आप कन्क्लूड करिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर सुना जाए ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : सुन लिया, अब आपको खत्म करना है ।

श्री राम अवधेश सिंह : यह कोई न्याय नहीं है । आपने एक आदमी को 40–50 मिनट दिए और मैं 5 मिनट भी नहीं बोल पाया और आप कह रहे हैं कि चुप हो जाइये ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : यह पर्सनल कंपीटीशन की बात नहीं है । आप अपनी बात कहिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने अच्छी बात कही है। मैं बोलूंगा तो आप सुनेंगे कि इनसे मैं कोई खराब बात नहीं बोलता।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : नहीं-नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : क्योंकि इन्होंने जो बात कही है भारत को जोड़ने का एक नमूना है काश्मीर सेकुलरिज्म का नमूना है काश्मीर और उसको खंडित करने की सारी बात कही। उन्होंने जो पहली बात कही कि यह जो खुराफात करने वाले लोग हैं, उनका सफाया किया जाये। वहां कौन खुराफात कर रहे हैं? किन कारणों से खुराफात कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या इंटरनल कारण है या कुछ बाहरी भी कारण है, इन तमाम बातों के बारे में हम को सोचना होगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में पश्चिमी राष्ट्रों के साम्राज्यवादी मुल्कों ने तीन नकेल डाली हैं। एक नकेल का नाम है इजरायल, दूसरी नकेल का नाम है काश्मीर और तीसरी का नाम है ताइवान। ये तीनों नकेल साम्राज्यवादियों ने डालकर रखी है।

एक माननीय सदस्य : यह नकेल क्या है?

श्री लक्ष्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): वह बिहार में है।

श्री राम अवधेश सिंह : आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। काश्मीर के माध्यम से ये साम्राज्यवादी मुल्क पाकिस्तान के द्वारा दबाव डालना चाहते हैं काश्मीर में। यह खुराफात अपने आप बंद हो जाये, अगर वहां पाकिस्तान का हस्तक्षेप बंद हो जाय यह खुराफात तो अपने आप मर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के माध्यम से पश्चिमी साम्राज्यवादी मुल्क खुराफात करा रहे हैं। काश्मीर में दस्ते भेज रहे हैं। जब हमने पूर्वी पाकिस्तान में और अब के बांग्लादेश में हमने भेजे थे अपने सिपाहियों को लंगी पहनाकर, उस समय हमें अच्छा लगा था, लेकिन जब ब भेज रहे हैं तो हमको बरा क्यों लग रहा है? अब हमको अलर्ट रहना पड़ेगा उनको कुचलना होगा, लेकिन केवल यह बात कहकर नहीं बल्कि हमको डिप्लोमेटिक स्तर पर भी इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी०ठाकुर) : राम अवधेश जी, आपको काश्मीर बजट पर ज्यादा समय मिल जाएगा, अब आप एक मिनिट में खत्म कीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि साम्राज्यवादी मुल्कों ने दुनिया को तोड़ने की कोशिश की है। पहले रूस को तोड़ा, जर्मनी को तोड़ा, वियतनाम को तोड़ा, हिंदुस्तान को तोड़ा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, वहां नयी प्रक्रिया शुरू करनी होगी .... **(व्यवधान)** और इस समस्या का समाधान करना होगा। वह हम केवल गोली या बंदूक से नहीं कर सकते बल्कि चुनाव के जरिए वहां एक पापुलर सरकार दीजिए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Mr. David Ledger. Please co-operate and finish in two minutes because then there is going to be a reply also and then voting.

SHRI DAVID LEDGER (Assam) : Mr. Vice-Cairman, the problem of Kashmir has dragged on for the past many years and today it has become more intense, more acute and more explosive than it ever was. The issue has been debated and discussed within and outside Parliament. Various ideas and proposals have been tossed into the air but a solution has remained elusive. The more one thinks about the situation in Kashmir, the more is one reminded of the series of mistakes which our political leaders have committed in relation to the problem of Kashmir. The Government of India, I am constrained to say, has followed but one policy so far, a policy of drift, and that policy has been consistently followed and as a result of this policy of drift today Kashmir has drifted to disaster. The wrong policies followed by the Government and the mistakes committed by our political leaders has resulted in a total erosion of the faith of the Kashmiris in the political system of this country, and what is alarming is that the

[Shri David Ledger]

uprise in Kashmir is not against any particular Government or against any particular political party which has formed the Government. The uprise in Kashmir is against India, everything Indian and everything which represents India. And what is even more disquieting.....

THE VICE-CHAIRMAN : Please co-operate, we have to conclude.

SHRI DAVID LEDGER : Let me make my concluding remark. What is even more disquieting is that this sentiment has the popular endorsement in Kashmir. One has only to speak to a Kashmiri youth to get an inkling of the anger that is in him. One has only to speak to a Kashmiri youngster to get an idea of the anger that is in him. It is so palpable.

Sir, the role of political parties in this connection has been the most disappointing. With due respect to the political parties, I would like to submit that the role of all the political parties in the country has been utterly disappointing. Every party has tried to derive political mileage, out of the situation in Kashmir. One party has been busy installing puppet Governments and apointing pliable Governors. The other party has been busy in going all the way to Kashmir and kissing the soil of Kashmir, in the name of preaching the message of so called love and hoisting the tricolour at Lal Chowk as if the national flag was never hoisted there.

There was never any sincere effort to analyse the situation in Kashmir in its proper historical background and perspective. No wonder, therefore, that the people in Kashmir feel let down and feel betrayed. The common man in Kashmir has, so far, been a mute spectator to an administration which is corrupt to the hilt. He has suffered from the stagnation of economic development. He has gone through the nightmare of the operation by the security forces. He has reeled under the heavy burden of unemployment. The future of the common man in Kashmir is, as it were, totally uncertain.

To add fuel to the fire is the role of Pakistan. The role of Pakistan in relation to the affairs in Kashmir has become a major factor. To say that the role of Pakistan has been dubious and reactionary from the very start, to say that it has been overtly and covertly encouraging and aiding terrorist and secessionist activities in the Valley is to state the obvious. It is an open secret. There is no need to mention it.

Pakistan has done its best to internationalise the issue in each and every forum of the world. It has even taken refuge under outdated U.N. Resolutions. The recent *bandh* organised in Pakistan, at the behest of Prime Minister Nawaz Sharief has added a new dimension to the whole problem. It is time the Government of India takes a serious note of it and have a serious talk with the Government in Pakistan on its role and involvement in the affairs of Kashmir. The stand of the Government of India should be clear and unambiguous. The vicious propaganda campaign launched by Pakistan against India has to be effectively countered. Our own propaganda channels have to be activised and put to use. The various international fora have to be used. Sir, this matter has been discussed at length in the last meeting of the National Integration Council. It is time the Government of India takes some action in this regard.

Before I conclude I will just mkae one or two points. While we express our views on the situation in Kashmir, it is important that we realise that the most important thing to do is to win back the confidence of the people there. The faith if the common man in the political systema has to be restored. Delhi must—I

would like to put emphasis on this—resist the temptation of installing puppet Governments. Delhi must resist the temptation of capturing power in Kashmir through unscrupulous means. The practice of thrusting puppet Governments down the throats of the Kashmiri people, the practice of dumping pliable Governors down the throats of the Kashmiri people, must be given up. The common man in Kashmir has to be taken into confidence. He should be allowed to elect a Government of his own choice. Elections must be held there as early as possible, and all sections in Kashmir should be given an opportunity to participate in the elections. This is one risk which the Government of India has to take.

In conclusion, I would just say this. Repeated extensions of President's rule in Kashmir is not and cannot be, the answer. May I respectfully submit that there are, clearly, two aspects to the Kashmir problem ? One is political and the other is economic. While it is imperative that the speedy economic development of the Valley is a must, while the need to provide employment opportunities to the educated job-seekers, who constitute the most vulnerable section in so far as indoctrination to militancy is concerned, cannot be denied, it must be honestly realised that the restoration of the political process has to be the top of the Kashmir agenda. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR)) : Now, the hon. Minister of State for Home affairs to reply.

SHRI DIPEN GHOSH : Sir, it is 5 P. M. What about the Finance Minister's statement ?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : He is here. Please co-operate. Let us complete this first. Let the Home Minister reply.

5.00 P.M.

SHRI M. M. JACOB : I am in the hands of the House. You must allow me three or four minutes. I know, when 17 Members of this august House have participated in the discussion, three or four minutes for me to reply are certainly inadequate, but I know the statutory requirement of the time and the constraints before us. So, I will restrict myself to only one or two sentences, requesting the hon. Members to ratify the extension of the President's rule in Jammu and Kashmir.

I would like to refer to the speech of Shri Jagmohan. When I was listening to his speech I was reminded about one of the ladies, who is biographer of a book. She wrote to the Prime Minister in England for a preface to her book, and the Prime Minister wrote back after reading the book, that there are may things which I see are true in this book, but also I see many things here which are original. What is original is not true. What is true is not original. (*Interruptions*). Mr. Jagmohan startd with the statement that the politics of Kashmir is a politics of anti-India sentiments. My friend Ram Awadhesh Singh correctly gave the analysis that the politics of Kashmir is a conspiracy of international imperialism, just as it is in Palestine, or in Israel, similar is the situation in Kashmir. So, it was the desire of some of the countries to see that Kashmir issue remains as an active issue, as a sore and irritant to India. It is a true fact. So, distorting the whole thing and blaming the Kashmir leaders, as if they were playing a different game, is a very unfortunate statement. It is distortion of history. I leave it there. I do not want to say anything more. (*Interruptions*)

[The Deputy Chairman in the Chair]

I agree with it. I am thankful to the Member for the constructive suggestions. Action plan will be there. Normalisation is the first and foremost thing. After the normalisation in Kashmir we will be ready for election, but the first thing is normalisation. Normalisation requires firm and effective measures to check and prevent infiltrators coming to this country, sabotage happening in this country, there should be a firm hand to deal with this. Similarly, economic development of the State and the peoples' involvement in it is very necessary. I agree with many of the suggestions made here in that connection. There is no doubt about it.

I must compliment the para-military forces and our forces who are doing very good service. Those who are erring and commiting mistakes, we are charging cases against them. There are 79 cases prevailing against the para-military forces now. That shows the sincerity of the Government to see that the culprits are punished, they are not set free. But we have got limitations in handling certain situations.

Same way, I come to another point of human right activists throughout the world who are spreading the message that there are no human right in Kashmir. Sir,...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Madam, not Sir.

SHRI M. M. JACOB : I started with Sir.

THE DEPUTY CHAIRMAN : You end with 'Madam'.

SHRI M. M. JACOB : Madam, our Prime Minister gave very good analysis in the Security Council in New York recently about the approach. I reiterate and say that you have to define the human rights. I say, human right of the terrorists and not human rights. (*Interruptions*). I am closing all other points here and I request you to vote for extension of the President's rule.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall first put the amendment moved by Shri Shabbir Ahmad Salaria to vote. Mr. Salaria, are you pressing ?

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : I would like to speak on that. I have said that elections should be held in Kashmir in four months. If elections could be held in Assam or in Puniab where the conditions were not good, the State should also make efforts to hold elections in Kashmir also within four months.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is a good suggestion. Now, after this suggestion, are you pressing or withdrawing your amendment ? ...(*Interruptions*)...

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : If the honourable Minister says that he will make efforts to have elections in Kashmir within a reasonable time, I am prepared to withdraw my amendment.

SHRI M. M. JACOB : Efforts will be made to normalize the situation in Kashmir and elections will be held after normalization.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Then I won't press my amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall now put the Statutory Resolution to vote. The question is :

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 18th July,

1990, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Jammu and Kashmir, for a further period of six months with effect from the 3rd March, 1992."

The motion was adopted.

CLARIFICATION RE. LETTER OF INTENT FROM THE FINANCE MINISTER TO PRESIDENT OF WORLD BANK

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH) : Madam Deputy Chairman, I am sorry I was not present this morning in the House when certain matters relating to my letter of intent to the President of the World Bank were raised. I take this opportunity to clarify the matter. Before I do so, I would like to say a few things.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar) : On a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes, what is the point of order ?

SHRI YAHWANT SINHA : The point of order is, is the Minister making a statement, in which case we have a right to seek clarifications ? Otherwise, he just lays it on the Table...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Okay, you lay it on the Table of the House, Mr. Minister...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : Otherwise there will be a clarification on a clarification.

SHRI YASHWANT SINHA : Yes, there may be a clarification on a clarification.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Okay, you lay it on the Table of the House if the Members so demand. Lay it on the Table of the House.

SHRI MANMOHAN SINGH : Madam, I lay a statement on the Table of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The House is adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adiourned at eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 28th February, 1992.

MGIPMRND—D— 863Rs.—18-5-1993—400